नई दिल्ली
04
सितंबर, 2026
शुक्रवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 155

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

अब डरहम की ओर से काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे मयंक 07

संक्षिप्त वार्ता

डॉल्फिन की धूम, 193 बार नहीं बल्कि 193 डॉल्फिन का हुआ दीदार

अहमदाबाद। गुजरात के दक्षिण कच्छ की खाड़ी में डॉल्फिन सबसे अधिक देखे जाने वाले समुद्री स्तनधारी जीव के रूप में उभरी हैं। गुजरात वन विभाग के अधीन स्वायत्त संस्था गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जीईईआर-गीर) फाउंडेशन ने अक्टूबर 2023 से फरवरी 2025 के दौरान दक्षिण कच्छ की खाड़ी में स्थित मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के दौरान शोधकताओं को 64 बार डॉल्फिन दिखाई दीं और कुल 193 डॉल्फिन देखी गईं।

यह अध्ययन गीर फाउंडेशन द्वारा किया गया था। ह्यस्टेटस सर्वे ऑफ डुगोंग एंड अदर मरीन मैमल्स, एंड इकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ सीग्रास हैबिटेट्स अराउंड नरारा एंड एडजसेंट आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छह्व नामक यह अध्ययन देश के पहले समुद्री संरक्षित क्षेत्र मरीन नेशनल पार्क और मरीन सेंचुरी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं।

होर्मुज पर तनाव: अमेरिका ने रोके 86 जहाज, हूती भी दाग रहे मिसाइलें

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा गतिरोध अब बेहद खतरनाक दौर में पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की खुली धमकियां दी हैं, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। हालिया हफ्तों में दोनों देशों के बीच हुए भीषण टकराव ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस संघर्ष के केंद्र में दक्षिणी ईरान के एक शादी समारोह पर हुआ वह हमला है, जिसे ईरान ने सीधा युद्ध अपराध करार दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनकी सेना ने रात के वक्त ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाकर भारी हमले किए। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका इस तरह की और कार्रवाई कर सकता है। इस बीच, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलने की घोषणा पर उन्हें तीखी आलोचना के बाद पीछे हटना पड़ा था। दूसरी ओर, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख मोहसेन रेजाई ने चेतावनी दी है कि तेहरान अब अमेरिका से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाएगा, जो अमेरिकी व्यवस्था को हिला सकती है।

कांगो में तेजी से फैल रहा इबोला, अब तक 3000 से ज्यादा मौतें

बुनिया। कांगो में इबोला वायरस आम लोगों पर कहर बरसा रहा है। यह बेहद तेजी से फैल रहा है। जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6,186 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3,007 लोगों की मौत हो चुकी है। यह इबोला का अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रकोप बताया जा रहा है। वायरस जिस गति से फैल रहा है, उसके मुकाबले इसे ट्रैक करने और रोकने के प्रयास पीछे रह गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इबोला का सबसे ज्यादा कहर इटुरी प्रांत में दिख रहा है। वहां से भागकर आए लोगों का कहना है कि स्वास्थ्यकर्मी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। संक्रमित लोगों के शवों को भी ठीक तरीके से संभाला नहीं जा रहा था।

केंद्रीय मंत्री गडकरी का राज्यों से आह्वान

बाइक टैक्सी को मंजूरी दें, 8 करोड़ रोजगार का वादा

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों से बाइक टैक्सी को तुरंत मंजूरी देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा खासकर ग्रामीण इलाकों में करीब 8 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के व्यापक मौका पैदा कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन परिवहन राज्य का विषय होने के कारण कुछ राज्यों में इसकी अनुमति अभी बाकी है, जिससे लोगों को कमाई का एक नया जरिया मिल सके।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नेगेटिव पॉइंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। उन्होंने भारी वाहन और निर्माण उपकरण चलाने वाले ड्राइवरों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण पर बल दिया, कंपनियों से उपकरण देने से पहले चालकों को प्रशिक्षित करने की अपील की।

इस कड़ी में, केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा नामक एक पायलट प्रोग्राम की शुरूआत की, जिसके तहत हाईवे, खनन और निर्माण जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों से जुड़े 10 लाख ड्राइवरों व कर्मचारियों की मुफ्त मेडिकल जांच और परामर्श मिलेगा। पहले चरण में नागपुर-कामठी और चंद्रपुर में 10 हजार लोगों की जांच का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने चिंता जाहिर की कि भारत में दोपहिया हादसों में 81,780 मौतें हुई हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं। सीट बेल्ट न लगाना, हिट एंड रन, गलत दिशा में ड्राइविंग, शराब और मोबाइल का इस्तेमाल इसके प्रमुख कारण हैं। उन्होंने इन आंकड़ों को देखकर वाहन चालकों के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता पर जोर दिया।

मायावती ने आकाश आनंद को बताया अपरिपक्व, यूपी में नहीं मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती ने लखनऊ में पार्टी की आल इंडिया बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों को पिछले कार्यों की समीक्षा व भविष्य की रणनीतियों पर निर्देश दिए। बैठक का एक प्रमुख बिंदु उनके भतीजे आकाश आनंद को लेकर रहा, जिसे मायावती ने अभी अपरिपक्व बताया और उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से इंकार किया। पूर्व सीएम मायावती ने स्पष्ट किया कि आकाश आनंद को अभी और अधिक परिपक्व होने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि विरोधियों द्वारा साम, दाम, दंड, भेद जैसे हथकंडों का इस्तेमाल कर चुनाव में पार्टी को हानि पहुंचाने से बचने के लिए यह कदम उठाना समय की मांग है।

नालसार यूनिवर्सिटी विवाद में बीसीआई के दो नोटिफिकेशन रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के व्यवहार और गतिविधियों को रेगुलेट करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

शीर्ष अदालत ने हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (नालसार) के छात्रों के खिलाफ बीसीआई द्वारा जारी किए गए दो विवादास्पद नोटिफिकेशन्स को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।

यह पूरा विवाद नालसार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने के विरोध से शुरू हुआ था। विश्वविद्यालय के विभिन्न बैचों के छात्रों ने सीजेआई द्वारा पुलिस कार्रवाई से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए इस निमंत्रण पर पुनर्विचार की मांग की थी। छात्रों का कहना था कि उनका विरोध संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है और वे न्यायिक पद का सम्मान करते हैं।

बीसीआई का विवादित रुख और वकीलों का विरोध

इस विरोध प्रदर्शन से नाराज होकर बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने शुरूआत में एक कड़ा निर्देश जारी कर दिया था। इसमें कहा गया था कि नालसार के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स को देश के किसी भी राज्य बार काउंसिल में वकील के तौर पर एनरोल नहीं किया जाएगा। बीसीआई ने आरोप लगाया था कि छात्रों में देश के सर्वोच्च न्यायिक पद के प्रति आदर नहीं है। हालांकि, कानूनी बिरादरी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा इसे 'मनमाना और गैर-कानूनी' बताए जाने के बाद बीसीआई को अपने कड़े रुख से पीछे हटना पड़ा और बाद में निर्देश वापस लेना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बीसीआई का काम केवल वकीलों के पेशेवर मानकों और लीगल एजुकेशन की रूपरेखा तय करना है। किसी यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रों के विरोध या व्यवहार को नियंत्रित करने का अधिकार बीसीआई के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। कोर्ट के इस निर्णय से नालसार यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

पंजाब में मतदाता सूची से नाम हटने पर राघव चड्ढा ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध

वेब वार्ता, नई दिल्ली। पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम हटने के बाद सियासत गरमा गई है। चड्ढा ने आरोप लगाया है कि मोहाली स्थित उनके मतदाता पहचान पत्र को जानबूझकर 'शिफ्टेड' (दूसरी जगह चले गए) के रूप में चिन्हित किया गया है, जो राजनीतिक बदले की भावना का स्पष्ट उदाहरण है।

चड्ढा ने सोशल मीडिया पर इस जानकारी को साझा करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने साफ किया कि यह केवल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है और वे नियमों के तहत 'दावे और आपत्तियां' दर्ज कराकर इसे दुरुस्त करवा रहे हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अक्टूबर 2026 में होना है। सांसद चड्ढा ने इसे प्रशासनिक त्रुटि मानने से इनकार करते हुए कहा कि जमीनी स्तर के बीएलओ से लेकर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) तक सभी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी आप सरकार के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव ड्यूटी खत्म होने के बाद अधिकारियों के तबादले और करियर का नियंत्रण राज्य सरकार के पास ही होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब से राज्यसभा सांसद होने के बावजूद उनका नाम किस आधार पर 'शिफ्टेड' चिन्हित किया गया, इसका सत्यापन उच्च स्तर पर सरकार के इशारे पर किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद से पंजाब में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का किया सफल परीक्षण

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (एलआरजीबी) खगांतक-243 का सफल ड्रॉप टेस्ट किया है। इस परीक्षण से भारतीय वायुसेना की दूर से सटीक हमला करने की क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। करीब 300 किलोग्राम वजनी इस ग्लाइड बम में 125 किलोग्राम का एमके-81 वॉरहेड लगाया गया है। इसकी मारक क्षमता करीब 144 से 180 किलोमीटर बताई गई है।

झारखंड में स्वाइन फ्लू का बढ़ता प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

रांची। झारखंड में पिछले 30 दिनों में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) संक्रमण के 36 मामले सामने आने से स्वास्थ्य महकमा चिंतित है और पूरी तरह अलर्ट हुआ है। इन मामलों में से 18 मरीज बच्चे और किशोर हैं, जिससे चिंता और बढ़ गई है। बढ़ते खतरे को देखकर राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

संक्रमण के प्रसार का एक प्रमुख कारण दूसरे राज्यों से यात्रा कर लौटने वाले लोग बताए जा रहे हैं। दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मौसमी फ्लू के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखकर झारखंड में अंतरराज्यीय आवाजाही पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस स्टैंडों जैसे उच्च आवाजाही वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, साथ ही जिला स्तर से रोजाना रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। राज्य में संक्रमण की सटीक पहचान के लिए रांची स्थित रिम्स और जमशेदपुर स्थित एमजीएम में एच1एन1 तथा एच3एन2 वायरस की जांच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को संदिग्ध मरीजों की त्वरित पहचान, जांच और समुचित इलाज सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सदर अस्पतालों में कम से कम 10-10 अतिरिक्त बेड आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई, आवश्यक दवाइयों का स्टॉक, आईसीयू/एचडीयू तथा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

कार्गो में धुएं के अलार्म...लखनऊ में एयर इंडिया एक्सप्रेस की इमरजेंसी लैंडिंग

वेब वार्ता, लखनऊ

वाराणसी से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (आईएक्स 1253) की गुरुवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान अचानक विमान के कार्गो कंपार्टमेंट में स्मोक इंडिकेशन (धुएं का अलार्म) बजने लगा था।

स्मोक इंडिकेशन का अलार्म बजते ही पायलट ने तत्परता दिखाते हुए लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क साधा और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इसके बाद सुबह करीब 8:52 बजे विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया।

लैंडिंग के तुरंत बाद एयरपोर्ट की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, अग्निशमन दल और तकनीकी विशेषज्ञों ने स्थिति को संभाला। विमान को स्टैंड पर पार्क कराकर सुबह 9:02 बजे तक सभी 155 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंजीनियरों और सुरक्षा टीमों द्वारा विमान का बारीकी से निरीक्षण किया गया। प्राथमिक जांच में विमान के भीतर धुआं या आग का कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

155 यात्री सुरक्षित, वाराणसी से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट

नेपाल में बाढ़ के बाद: 22 लाख टन मलबे का पहाड़, सफाई में लगेंगे सालों

वेब वार्ता, काठमांडू। 26 अगस्त को नेपाल की भोटेकोशी-त्रिशूली नदी में ग्लेशियर ढहने के बाद आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल जान-माल का भारी नुकसान किया है, बल्कि अपने पीछे 22 लाख टन से अधिक मलबे का एक विशाल पहाड़ छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के शुरूआती आकलन के अनुसार, यह मलबा इतना अधिक है कि इसे हटाने के लिए 22,000 बड़े ट्रकों की आवश्यकता होगी, और इसकी सफाई में कई साल लग सकते हैं।

इस विनाशकारी बाढ़ का मानवीय टोल भी भयावह है। नेपाल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इस त्रासदी में 1,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जबकि लगभग 4,000 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दलों ने अब तक 10,451 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जो मलबा बचा है, उसका अनुमानित वजन लगभग 22 लाख टन है। इसे समझने के लिए, कल्पना कीजिए कि अगर आप एक के बाद एक ट्रक खड़े करें, तो यह कतार कई किलोमीटर लंबी होगी। या अगर इसे ओलंपिक स्विमिंग पूल (जो 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा होता है) में भरा जाए, तो करीब 440 ऐसे पूल भर जाएंगे। हालांकि, ये तुलनाएं केवल मलबे की विशालता का एक अनुमान देने के लिए हैं।

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह मलबा केवल मिट्टी या गाद नहीं है, इसमें ढही हुई इमारतों के कंक्रीट और ईंटों के टुकड़े, विशाल चट्टानें, उखड़े हुए पेड़-पौधे और घरों का सामान सब कुछ मिला हुआ है। यूएनडीपी ने अपने रैपिड असेसमेंट एंड एनालिसिस फॉर इमीडिएट रिकवरी सिस्टम और यूरोपियन सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके मलबे का खाका तैयार किया है, जिससे पता चला है कि 2,359 ढहे हुए मकानों से ही लगभग 5.5 लाख टन इमारती मलबा निकला है। बाकी मलबे में प्राकृतिक और घरेलू कचरा शामिल है। इस मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनें, हजारों ट्रक और बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होगी।

जोखिम भरा हो गया है

सरकार का अनुमान है कि सफाई और पुनर्निर्माण में कई साल लग सकते हैं, क्योंकि कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं और वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। यह मलबा बचाव कार्यों में भी बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिससे रेस्क्यू टीमों के लिए रास्ते साफ करना बेहद जोखिम भरा हो गया है।

पुर्ननिर्माण का रास्ता लंबा और कठिन होगा

बाढ़ का सबसे बड़ा असर उन इलाकों पर पड़ा है, जहां की आबादी पहले से ही आजीविका और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थी। छह जिलों की 17 नगर पालिकाओं में कुल 84,270 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में 67 .4 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, और जून से सितंबर के बीच नेपाल का मुख्य मॉनसून बुवाई का सीजन होता है। ऐसे में फसलें, पशुधन और कृषि भूमि के तबाह होने से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसके अलावा, 431 .1 मेगावाट क्षमता वाले 11 हाइड्रो पावर और 1 सोलर प्लांट ठप हो गए हैं, और निमार्णाधीन 15 अन्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (470 मेगावाट) भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। नेपाल में यूएनडीपी की आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुका ने कहा कि यह त्रिशूली कॉरिडोर के समुदायों के लिए एक विनाशकारी आपदा है, जहाँ लोगों ने अपनों, अपने घरों और आजीविका को खो दिया है। उनकी प्राथमिकता है कि राहत सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे ताकि वे सुरक्षित रूप से फिर से अपना जीवन शुरू कर सकें। पुनर्निर्माण का रास्ता लंबा और कठिन होगा।

संपादकीय

मृत नहीं, बम-बम आर्थिकी

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की आर्थिक विकास दर 7.8 फीसदी आंकी गई है। हम इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि यह भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अर्थशास्त्रियों का निष्कर्ष है। यह विकास दर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईरान युद्ध का कालखंड रहा है। युद्ध के कारण तेल-गैस, उर्वरक, खाद्य और अन्य सामान के संकट दुनिया ने झेले हैं और युद्ध अब भी जारी है। सप्लाई चेन अब भी बाधित है। होर्मुज जलडमरूमध्य अब भी लगभग बंद है। ईरान का डंडा चल रहा है, बेशक अमरीका कुछ भी दावे करे। युद्ध के अलावा, अल-नीनो और टंपवादी टैरिफ के प्रभाव भी रहे हैं, लिहाजा भारत की वास्तविक जीडीपी की यह दर और नॉमिनल जीडीपी की 10.3 फीसदी विकास दर, यकीनन, बेहतर अर्थव्यवस्था के प्रमाण हैं। यकीनन देश प्रगति कर रहा है। जीएसटी संग्रह भी 1.99 लाख करोड़ रुपए, यकीनन, एक रिकॉर्ड है। कमोबेश भारत की अर्थव्यवस्था मृत नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति टंप ने उगला था। बाद में नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी ने न केवल मृत अर्थव्यवस्था करार दिया, बल्कि ह्यआर्थिक सुनामी की भविष्यवाणी भी की। देश ने दोनों को ही गंभीरता से नहीं लिया और अब विकास की सुनामी का यथार्थ सामने है। भारत का खनन क्षेत्र नकारात्मक (-2.4 फीसदी) रहा है, लेकिन कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग, निर्माण, सर्विस, व्यापार, होटल, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन आदि क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि पिछले साल की तुलना में कृषि की विकास दर ने 0.8 फीसदी का गोता खाया है, फिर भी यह 3.6 फीसदी रही है। मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र में बढ़ोतरी क्रमश: 10.7 और 10 फीसदी दर्ज की गई है। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर भी 5.2 फीसदी आंकी गई है। जीडीपी गणना की प्रक्रिया और प्रणाली पर प्रख्यात अर्थशास्त्रियों ने लगातार सवाल उठाए हैं।

वे इसमें 2.5 फीसदी के फर्जीवाड़े का आकलन करते रहे हैं। हम फिलहाल इस विवाद को यहीं छोड़ते हैं। जीडीपी की विकास दर को स्वीकार करते हुए कुछ जिज्ञासाएं पेश करना चाहते हैं। हम महंगाई, गरीबी, करीब 81.5 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज जैसे मुद्दे भी छोड़ते हैं, क्योंकि एक वर्ग इन मुद्दों को विकास दर में घुसाना आर्थिक निरक्षरता मानता है। बहरहाल सवाल और जिज्ञासा यह है कि जीडीपी के ये आंकड़े देश के शीर्ष 100 अरबपतियों की तीन गुना बढ़ी संपत्तियों की बदौलत हैं अथवा इसमें देश के कामकाजी वर्ग, श्रम-बल, निजी खपत और निवेश के भी आंकड़े शामिल हैं? यदि हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग यही रही है या 7 फीसदी के करीब रही है, तो देश की प्रति व्यक्ति आय 2.35 लाख-2.72 लाख रुपए के बीच क्यों है? भारत दुनिया में 144-149वें स्थान तक क्यों रहता है? जर्मनी और जापान की प्रति व्यक्ति आय क्रमश: करीब 54-55 लाख रुपए और 29-30 लाख रुपए है। दोनों देश तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। कोई तुलना है क्या? क्रय-शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर भी भारत 121-125वें स्थान पर क्यों है? भारत और जापान की जीडीपी में कोई खास अंतर नहीं है। बहरहाल आर्थिक असमानता की यह खाई कब तक भरी जाएगी? अरबपतियों की दौलत तो बढ़ती रहेगी, लेकिन आम आदमी की औसत आमदनी 1 फीसदी भी क्यों नहीं बढ़ पाई है? यदि प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों का तार्किक जवाब दे पाएंगे, तो देश भी उनकी बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार कर लेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही, 18-29 साल के आयु-वर्ग के 14.8 फीसदी युवा बेरोजगार हैं। डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त 29.4 फीसदी युवाओं के पास निश्चित, स्थिर काम नहीं है।

नीट श्रेणी के 40.1 फीसदी युवा बेरोजगार हैं। क्या इनसे भयावह यथार्थ कोई और हो सकता है? बेशक सरकार दावा कर रही है कि देश की बेरोजगारी दर 5.1 फीसदी है। यदि युवा जैसी सबसे उर्वर आयु और जमात बेरोजगार है, तो कौन-सी आर्थिकी बम-बम है? एक और डराने वाला आंकड़ा सामने आया है कि करीब 8 करोड़ लोग वापस कृषि की ओर चले गए हैं। वे रोजगार में हैं अथवा बेरोजगार हैं, सरकार और नीति आयोग स्पष्ट करें। बेशक शेयर बाजार में विदेशी निवेशक बढ़े हैं, बीते एक साल में करीब 30 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है, देश में 18 करोड़ ईपीएफ के नए खाते खुले हैं, लेकिन अभी यह विकास आश्वस्त करने वाला नहीं है। देश के आर्थिक विकास के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारों के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं कि सभी को सरकारी रोजगार दिया जा सके। इसलिए सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना होगा, ताकि वह युवाओं को वांछित संख्या में रोजगार दे सके। युवाओं का प्रशिक्षण इस तरह करना होगा, कि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें। दसवीं के बाद ही यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि युवा रोजगार के अनुकूल प्रशिक्षण पा सकें। तभी सच्चे अर्थों में भारत का विकास होगा।

ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का

कुछ छोटे-छोटे अभ्यास हमारा जीवन बदल सकते हैं। प्रतिदिन खुलकर हंसें। प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकालें। जीवन के सभी उपहारों के लिए हर रोज शुक्रिया अदा करें। हर रोज कुछ न कुछ अच्छा होता ही है, उसके लिए शुक्रगुजार हों। तुलना को थोड़ा कम करें। कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया करते रहें। कभी किसी की निस्वार्थ सहायता कर दें। सबसे बड़ी बात, परिवार के साथ बिना किसी स्क्रीन के बैठें और मोबाइल की स्क्रीन से अधिक जीवन के दृश्य देखें। धीरे-धीरे हम खुद-ब-खुद जान जाएंगे और अनुभव कर लेंगे कि आनंद खरीदा नहीं जाता, वह विकसित किया जाता है।

हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं। कोई धन चाहता है, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई सुरक्षा, तो कोई अमर होने जैसा नाम। लेकिन इस दौड़ में एक विचित्र विडंबना यह है कि हम में से अधिकांश लोग जीने की तैयारी करते-करते पूरा जीवन बिता देते हैं। हम घर बना लेते हैं, पर उसमें रहने का समय नहीं निकाल पाते। हम साधन जुटा लेते हैं, पर उनका आनंद नहीं ले पाते। हम भविष्य को सुरक्षित करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वर्तमान हमारी मुी में से रेत की तरह फिसल जाता है। शायद इसी कारण संसार में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं। प्रश्न यह नहीं कि हमारे पास धन कितना, सोना कितना है, भवन कितने हैं, नौकर-चाकर कितने हैं, सुविधाएं कितनी हैं, प्रश्न यह है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे कितनी गहराई से जी पा रहे हैं। सच तो यह है कि संसार उस व्यक्ति का नहीं जिसके पास सबसे अधिक है, बल्कि उसका है जो जीवन का सबसे अधिक रस ले पाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम ह्यआनंदह्व शब्द का असली मतलब समझें। आनंद का अर्थ उच्छृंखल मनोरंजन या क्षणिक मौज-मस्ती नहीं है। आनंद का अर्थ है, वर्तमान क्षण के साथ पूरी सजगता से उपस्थित होना। एक कप चाय को केवल पीना नहीं, उसका स्वाद महसूस करना। वर्षा को केवल मौसम न मानना, बल्कि उसकी बूंदों की धुन सुनना। परिवार के साथ बैठना केवल औपचारिकता न हो, बल्कि आत्मीयता का उत्सव बने।

जीवन का आनंद उन्हीं को मिलता है जो अनुभवों को जीते हैं, केवल घटनाओं को घटित नहीं होने देते। जीवन से संघर्ष करने वाला व्यक्ति थक जाता है, जीवन के साथ सहयोग करने वाला व्यक्ति खिल उठता है। सवाल यह है कि बेशुमार धन, सारी सुविधाओं और सारे सुखों के बावजूद अक्सर हम आनंद से वंचित क्यों रह जाते हैं? इसका उत्तर बाहर नहीं, हमारे मन की संरचना में छिपा है। हम तुलना करते हैं, प्रतिस्पर्धा में उलझते हैं, ईर्ष्या पालते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत का बोझ ढोते हैं और अपने निर्णय भी अक्सर इस आधार पर लेते हैं कि ह्यलोग क्या कहेंगे?ह्व परिणाम यह होता है कि हमारा ध्यान जीवन पर नहीं, दूसरों के जीवन पर अधिक रहने लगता है। जिस क्षण तुलना शुरू होती है, उसी क्षण आनंद समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुलना हमें हमारी कमी दिखाती है, जबकि आनंद हमें हमारे पास जो है, उसकी समृद्धि का अनुभव कराता है।

आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी अब इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं। जब हमें कोई उपलब्धि मिलती है, तो मस्तिष्क में डोपामीन सक्रिय होता है। यह उत्साह देता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। इसलिए अगली उपलब्धि की भूख जल्दी ही पैदा हो जाती है। इसके विपरीत सेरोटोनिन संतोष, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता से जुड़ा है। यही कारण है कि उपलब्धियों से अधिक अर्थपूर्ण जीवन और स्वस्थ संबंध व्यक्ति को दीर्घकालिक प्रसन्नता देते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान के अग्रणी विद्वान मार्टिन सेलिगमैन ने भी अपने शोधों में दिखाया कि खुशी केवल सुखद अनुभवों से नहीं, बल्कि उद्देश्य, संबंध, उपलब्धि और अर्थपूर्ण जीवन से बनती है। सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख स्तभों में गिने जाने वाले विश्व प्रसिद्ध हंगेरियन-अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने ह्यफ्लो स्टेटह्व का सिद्धांत दिया, जिसमें व्यक्ति किसी सार्थक कार्य में इतना डूब जाता है कि समय का बोध भी कम हो जाता है। यही अवस्था आनंद के सबसे प्रामाणिक अनुभवों में से एक मानी जाती है। आज न्यूरोसाइंस यह भी प्रमाणित कर चुका है कि कृतज्ञता का नियमित अभ्यास मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। इसका अर्थ यह है कि धन्यवाद कहना केवल संस्कार नहीं, मस्तिष्क के लिए भी एक स्वस्थ अभ्यास है। आइये, अब हम खुद से ही पूछते हैं कि दुनिया वास्तव में किसकी है? क्या केवल सबसे अमीर व्यक्ति की? क्या सबसे शक्तिशाली की? क्या सबसे प्रसिद्ध की? यदि ऐसा होता, तो संसार के सभी धनवान सबसे अधिक प्रसन्न होते। वास्तविकता इसके विपरीत है। अगर सबसे अमीर, सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही खुशियां बांट सकता तो बिल गेट्स का अपनी पत्न ी मेलिंडा गेट्स से अलगाव न होता, मेलिंडा गेट्स दुनिया के इस सर्वाधिक अमीरों में गिने जाने वाले और अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति को छोडकर उससे अलग न हो जाती। सच तो यह है कि दुनिया तो उसकी है जो सुबह उगते सूर्य को देखकर मुस्कुरा सकता है।

जिसकी आंखें वर्षा की पहली बूंदों में संगीत सुन लेती हैं। जिसे बच्चों की खिलखिलाहट किसी पुरस्कार से अधिक मूल्यवान लगती है। जिसे हवा का स्पर्श, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों का कलरव अभी भी चमत्कार प्रतीत होता है। जिसके भीतर विस्मय जीवित है, उसी के भीतर आनंद भी जीवित है। भारतीय चिंतन सदियों से कहता आया है कि वर्तमान क्षण ही जीवन है। न बीता हुआ कल लौट सकता है, न आने वाला कल अभी अस्तित्व में है। आनंद कोई उपलब्धि नहीं, चेतना की एक अवस्था है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखने की दृष्टि अवश्य हमारे हाथ में है। जब दृष्टि बदलती है, तो वही संसार नया दिखाई देने लगता है। इसलिए परिवर्तन की शुरूआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता में है। सौ वर्ष तक बोझ ढोने से अच्छा है कि कुछ वर्ष पूरे होश, पूरे प्रेम और पूरे उत्साह से जिए जाएं। जीवन किसी दंड का नाम नहीं है। यह एक दुर्लभ अवसर है। उत्सव बाहर आयोजित नहीं होते, उत्सव देखने वाली दृष्टि में जन्म लेते हैं।

अगर हमने अपने भीतर उत्सव जगा लिया है तो हमारे लिए साधारण दिन भी असाधारण हो जाते हैं। कुछ छोटे-छोटे अभ्यास हमारा जीवन बदल सकते हैं। प्रतिदिन खुलकर हंसें। प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकालें। जीवन के सभी उपहारों के लिए हर रोज शुक्रिया अदा करें। हर रोज कुछ न कुछ अच्छा होता ही है, उसके लिए शुक्रगुजार हों। तुलना को थोड़ा कम करें। कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया करते रहें। कभी किसी की निस्वार्थ सहायता कर दें। सबसे बड़ी बात, परिवार के साथ बिना किसी स्क्रीन के बैठें और मोबाइल की स्क्रीन से अधिक जीवन के दृश्य देखें। धीरे-धीरे हम खुद-ब-खुद जान जाएंगे और अनुभव कर लेंगे कि आनंद खरीदा नहीं जाता, वह विकसित किया जाता है। अंततः जीवन कोई परीक्षा नहीं, जिसमें हर समय स्वयं को सिद्ध करना पड़े। जीवन तो एक नृत्य है, एक संगीत है, एक उत्सव है। जीवन को पकड़ने की नहीं, उसके साथ बहने की आवश्यकता है। जिस दिन हम जीवन को भोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का अनुपम अवसर समझ लेंगे, उसी दिन यह दुनिया सचमुच हमारी हो जाएगी। तब यह पंक्ति जीवन का शाश्वत सूत्र बन जाएगी और हम आह्लादित होकर आनंद में गा उठेंगे कि ह्ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का, जो जी गया जीवन सच्ची खुशी का।

स्पिरिचुअल हीलर
हैपीनेस गुरु डा. प्रमोद निर्वाण
गिनीड्डा विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित लेखक

रूस अमेरिका सहित दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक संकट की आहट

अमेरिका की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई है। ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिका आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जिस तरह से टैरिफ नीतियों को लेकर यूरोप, नाटो सहित दुनिया के अधिकांश देशों के साथ जिस तरह की दादागिरी की। जिस तरह से ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, उससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति लगातार गड़बड़ाती चली गई।

अमेरिका में महंगाई बढ़ी तेजी के साथ बड़ी इसी बीच ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका को अहंकार था, वह 15 20 दिन में ईरान को ठिकाने लगा देंगे। ईरान को तो वह ठिकाने लगा नहीं पाए, उल्टे अरब देशों से अमेरिका के पैर उखड़ गए। सारे अमेरिकी सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। 70 फीसदी हथियार खत्म हो गए, जो डर और भय अमेरिका को लेकर सारी दुनिया में बना हुआ था, वह डर और भय भी खत्म हो गया। ट्रंप की नीतियों के कारण डॉलर का दबदबा भी सारी दुनिया से खत्म होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं से वैश्विक कारोबार शुरू हो चुका है। जिसके कारण अमेरिका आर्थिक रूप से विभिन्न कारणों से कमजोर होता चला जा रहा है। अमेरिका में महंगाई के कारण त्राहिमाम मचा हुआ है। कुछ इसी तरह की स्थिति रूस की भी है। पिछले कई वर्षों से यूक्रेन के साथ वह युद्ध लड़ रहा है। भारी आर्थिक एवं सामरित नुकसान रुस को उठाना पड़ा है। रूस की आर्थिक स्थिति भी तेजी से खराब हो रही है। उसे अपना सोना बेचना पड़ रहा है। इसके बाद भी युद्ध कब खत्म होगा इसका कोई अता पता नहीं है। रूस और अमेरिका का जो अहंकार था, वह यूक्रेन और ईरान ने एक तरह से तोड़ दिया है। रूस और अमेरिका को युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यही हाल इजराइल का हुआ है। उनका अहंकार उनके आड़े आ रहा है।

इसी बीच चीन ने बड़ी शांति के साथ जब दो महाशक्तियां और दुनिया के अधिकांश देश आपस में लड़ रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए व्यापार के जरिए अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को मजबूत कर लिया। चीन एक नई महाशक्ति के रूप में सारी दुनिया के सामने है। चीन के बिना किसी का काम नहीं चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति भारत की है। भारत दो पाटों के बीच में फंसकर बुरी तरह से पिस रहा है। भारत अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रचारित करके तथा सबसे बड़ा बाजार होने का अहंकार पालकर जिस तरह की गलतियां पिछले एक दशक से कर रहा है। उसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति भी दिनों दिन खराब होती जा रही है। सरकार कोई भी दावा करे, उन दावों के विपरीत भारत की आर्थिक स्थिति है। भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। भारत का सामरिक खर्च बढ़ता चला जा रहा है। 20 से 25 करोड युवा बेरोजगारी के शिकार हैं। गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। 80 करोड लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। इसके बाद भी भारत सरकार भी जिस तरह से रूस और अमेरिका अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ वही स्थिति भारत की देखने को मिल रही है। भारत चीन के ऊपर निर्भर होता चला जा रहा है।

चीन का आयात भारत में साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। उसके मुकाबले निर्यात घटता जा रहा है। भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा है। सीमा विवाद है, भारतीय सीमाओं पर चीन का अनधिकृत कब्जा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भी भारत सरकार चीन के सामने बेबस नजर आ रही है। अब आर्थिक स्थिति को संभालना और महंगाई से निपटना भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं अमेरिका, चीन, रूस के तीन पाटों के बीच में फंसकर भारत लगातार पिस रहा है। सभी महाशक्तियां भारत को अपने इशारे पर नचा रही हैं। भारत को उनके इशारों पर नाचना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति इसके पहले कभी नहीं थी। अब जिस तरह की आर्थिक मंदी की वैश्विक स्थिति बन रही है। उसने भारत की चिताओं को बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को वास्तविक सत्य के आधार पर अपनी नीतियां बनानी होगी। अहंकार से बाहर निकलना होगा। तभी जाकर स्थितियों में सुधार लाया जा सकता है।

(लेखक - सनत जैन)

तकनीक बदली, गुरु की भूमिका नहीं

भारतीय परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य कभी केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं रहा। गुरु-शिष्य परंपरा में ज्ञान के साथ संस्कार, अनुशासन, आत्मसंयम, सेवा, कर्तव्य और विवेक को महत्व दिया जाता था। महर्षि संदीपनि और श्रीकृष्ण, द्रोणाचार्य और अर्जुन, चाणक्य और चंद्रगुप्त तथा रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे उदाहरण बताते हैं कि गुरु केवल विषय का ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण करने वाला मार्गदर्शक होता है।

कबीर ने गुरु की इसी भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा था- ह्यगुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पांय। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन कक्षाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ज्ञान तक पहुंच को अभूतपूर्व रूप से आसान बना दिया है। कुछ सेकंड में किसी विषय की जानकारी हासिल की जा सकती है।

स्वयम (एसडब्लूएवाईएएम) और दीक्षा (डीआईकेएसएचए) जैसे डिजिटल मंचों ने शिक्षा को कक्षा और स्थान की सीमाओं से बाहर निकाला है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और अपार (एपीएएआर) जैसी व्यवस्थाएं उच्च शिक्षा को अधिक लचीला बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह तकनीकी परिवर्तन स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके बीच हमें एक बुनियादी अंतर समझना होगा- जानकारी और ज्ञान एक ही चीज नहीं हैं। इंटरनेट जानकारी दे सकता है, लेकिन यह नहीं सिखा सकता कि कौनसी जानकारी सही है और कौनसी भ्रामक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्तर तैयार कर सकती है, लेकिन यह तय नहीं कर सकती कि विद्यार्थी उस उत्तर का नैतिक और व्यावहारिक उपयोग कैसे करे। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म परीक्षा की तैयारी करा सकता है, लेकिन असफलता के बाद फिर खड़े होने का आत्मविश्वास नहीं दे सकता। मशीन विद्यार्थी की गलती बता सकती है, पर उसके पीछे छिपे डर, संकोच या आत्मविश्वास की कमी को समझने के लिए मानवीय संवेदना चाहिए। यही वह क्षेत्र है जहां शिक्षक की भूमिका तकनीक से ऊपर दिखाई देती है। विडंबना यह है कि शिक्षा का विस्तार जितना हुआ है, सीखने की गुणवत्ता की चुनौती उतनी ही गंभीर बनी हुई है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन डिग्री और रोजगार के बीच संबंध कमजोर रहा तो यह उपलब्धि अधूरी रह जाएगी। नई अर्थव्यवस्था को केवल डिग्रीधारी युवा नहीं, बल्कि ऐसे युवा चाहिए जो समस्या का समाधान कर सकें, तकनीक को समझ सकें, संवाद कर सकें, नए कौशल सीख सकें और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें। इसलिए विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और उद्योग की जरूरतों को शिक्षा से जोड़ना समय की मांग है। तकनीक के दौर में शिक्षक को भी बदलना होगा। यदि शिक्षक डिजिटल साधनों और एआई से दूरी बनाए रखेगा तो वह नई पीढ़ी से संवाद में पीछे रह सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि एआई शिक्षक का स्थान ले ले।

सही रास्ता दोनों के संतुलन में है। सोशल मीडिया की लगातार बढ़ती मौजूदगी, त्वरित सफलता की चाह, उपभोक्तावाद और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने बच्चों और युवाओं के सामने नई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे समय में शिक्षा यदि केवल अंक, रैंक और नौकरी तक सीमित रह गई तो समाज को कुशल पेशेवर तो मिल सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिकों की कमी बनी रह सकती है। सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहिष्णुता, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी जैसे मूल्य शिक्षा के मूल में होने चाहिए। शिक्षक का आचरण भी विद्यार्थियों के लिए किसी पाठ्यपुस्तक से कम प्रभावशाली नहीं होता। जिस शिक्षक में समय की पाबंदी, अनुशासन, ईमानदारी, संवेदना और सीखने की निरंतर इच्छा होगी, वह बिना किसी अलग नैतिक शिक्षा के भी विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखा देगा। शिक्षा पर पर्याप्त निवेश भी इस परिवर्तन की बुनियादी आवश्यकता है। अच्छे विद्यालय केवल भवन से नहीं बनते। पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल मैदान, इंटरनेट और डिजिटल उपकरण आवश्यक हैं, लेकिन उनसे अधिक आवश्यक है ऐसा शैक्षिक वातावरण जहां शिक्षक को सम्मान मिले और विद्यार्थी बिना भय के प्रश्न पूछ सके। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन शिक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी में जिज्ञासा, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। यहां गुरु की भूमिका निर्णायक है। तकनीक विद्यार्थी को दुनिया से जोड़ सकती है, लेकिन शिक्षक उसे अपने समाज और जिम्मेदारियों से जोड़ता है। तकनीक उसे सूचना दे सकती है, लेकिन गुरु उस सूचना को ज्ञान और ज्ञान को जीवन-दृष्टि में बदलने में सहायता करता है। आजादी के बाद भारत ने शिक्षा की पहुंच और विस्तार में असाधारण प्रगति की है। अब अगली मंजिल अधिक विद्यालय या अधिक डिग्रियां भर नहीं, बल्कि बेहतर सीखने, बेहतर कौशल और बेहतर चरित्र का निर्माण है। भारत को ऐसी शिक्षा चाहिए जो प्रयोगशाला में वैज्ञानिक, खेत में तकनीक समझने वाला किसान, उद्योग में कुशल युवा, समाज में संवेदनशील नागरिक और राष्ट्र के लिए जिम्मेदार मनुष्य तैयार करे।

इसलिए तकनीक का स्वागत पूरी शक्ति से होना चाहिए, लेकिन शिक्षक की भूमिका को उसके सामने छोटा करके नहीं। भविष्य की शिक्षा में स्मार्ट कक्षा हो सकती है, डिजिटल पुस्तकालय हो सकता है, एआई सहायक हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी के व्यक्तित्व को समझने वाला, उसकी क्षमता को पहचानने वाला और असफलता के समय उसका हाथ थामने वाला गुरु फिर भी आवश्यक रहेगा। तकनीक उत्तर खोज सकती है, गुरु सही प्रश्न करना सिखाता है। तकनीक ज्ञान तक पहुंच बना सकती है, गुरु उस ज्ञान को विवेक में बदलता है। इसलिए शिक्षा का भविष्य तकनीक और गुरु में किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों के सार्थक समन्वय में है। तकनीक बदलती रहेगी, साधन बदलते रहेंगे, लेकिन मनुष्य निर्माण में गुरु की भूमिका कभी पुरानी नहीं होगी।

अनुज आचार्य
लेखक बैजनाथ से हैं

आलेख

दुनिया जब बुरे दौर में है तब भारत के आर्थिक उजाले

दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है, वह आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से असाधारण चुनौतियों का दौर है। रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव, पश्चिम एशिया में तनाव, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने कठिन प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस मजबूती का परिचय दिया है, वह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलते भारत की सामर्थ्य का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को ऐसी उम्मीद के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी ओर दुनिया आश्चर्य और विश्वास दोनों के साथ देख रही है। इस विकास दर ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक शक्ति और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है एवं एक उजाला बिखेरा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वृद्धि ऐसे समय दर्ज हुई है, जब परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। महंगाई, ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पथ मजबूत बना रहा। पिछले वर्ष इसी तिमाही में विकास दर 6.9 प्रतिशत थी। यानी एक वर्ष में आर्थिक वृद्धि की गति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है। घरेलू मांग की मजबूती, सरकारी पूंजीगत व्यय, विनिर्माण, निर्माण और निर्यात जैसे क्षेत्रों का योगदान इस प्रदर्शन के पीछे महत्वपूर्ण रहा है।

आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है, जब उसे उसके वैश्विक संदर्भ में देखा जाए। आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं केवल आर्थिक नीतियों से प्रभावित नहीं हो रहीं, बल्कि युद्ध, कूटनीतिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंध भी उनकी दिशा तय कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का तनाव ऊर्जा बाजार और वैश्विक आपूर्ति तंत्र के लिए चिंता पैदा करता है। इन परिस्थितियों में भारत का अपेक्षाकृत तेज आर्थिक विकास यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए ऐसे मजबूत घरेलू आधार तैयार किए हैं, जो बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखते हैं। यही वह परिवर्तन है जो भारत को केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है। करोड़ों उपभोक्ताओं की मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, बुनियादी ढांचे पर निवेश और बदलती उपभोग संस्कृति ने अर्थव्यवस्था को आंतरिक गति प्रदान की है। जब वैश्विक बाजार अनिश्चित हों, तब घरेलू मांग अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा-कवच का काम करती है। इसीलिए वर्तमान विकास दर में घरेलू मांग की मजबूती को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

इस आर्थिक प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वृद्धि केवल एक क्षेत्र के सहारे नहीं टिकी है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारत धीरे-धीरे उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को मुख्यत: सेवा क्षेत्र की शक्ति के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब देश में उत्पादन बढ़ाने, घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में किए गए प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। निर्माण क्षेत्र भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, आवास, औद्योगिक गलियारे और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश का प्रभाव केवल आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, बल्कि उससे भविष्य की आर्थिक क्षमता भी निर्मित होती है।

भारत की वर्तमान आर्थिक यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई नीतियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, विनिर्माण, नए उद्यम, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया है। जनधन खातों से लेकर डिजिटल भुगतान तक और राजमार्गों से लेकर रेलवे के आधुनिकीकरण तक, आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक तंत्र तैयार हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर ने देश के बड़े बाजार को अधिक एकीकृत करने में भूमिका निभाई है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसी व्यवस्थाओं ने कारोबारी वातावरण को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने अनेक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और निवेश को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों का वास्तविक मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके परिणामों से होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत अवश्य देते हैं।

आम नागरिक के लिए आर्थिक विकास का अर्थ तभी सार्थक है, जब उसके जीवन में रोजगार के अवसर बढ़ें, आय में वृद्धि हो, महंगाई नियंत्रित रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार आए। सकल घरेलू उत्पाद हमें अर्थव्यवस्था की गति बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उस विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक किस प्रकार पहुंच रहा है। इसलिए भारत की अगली चुनौती तेज विकास से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी रोजगार है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का विस्तार इसलिए आशाजनक है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भविष्य में भारत को ऐसे उद्योगों की आवश्यकता होगी, जो बड़ी संख्या में युवाओं को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार दे सकें। भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि उसे कौशल, शिक्षा, तकनीक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं तो यही युवा शक्ति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी ऊर्जा बन सकती है।

भारत का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर बनना नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को इतना मजबूत करना है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके। आज दुनिया चीन के विकल्प के रूप में विभिन्न उत्पादन केंद्रों की तलाश कर रही है। भारत के पास विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन, तकनीकी क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी विशिष्ट ताकतें हैं। यदि भारत विनिर्माण, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं में अपनी क्षमता बढ़ाता है, तो वह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। 2047 का विकसित भारत केवल सरकार का संकल्प नहीं, बल्कि देशवासियों की सामूहिक आकांक्षा है। 7.8 प्रतिशत की विकास दर इस यात्रा में एक उत्साहजनक पड़ाव है, मंजिल नहीं। भारत को लगातार उच्च विकास दर, मजबूत वित्तीय व्यवस्था और स्थिर आर्थिक वातावरण के साथ-साथ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर भी समान ध्यान देना होगा।

भारत की आर्थिक कहानी अब केवल आंकड़ों की कहानी नहीं रह गई है। यह आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की कहानी बन रही है। दुनिया जब युद्ध और आर्थिक अस्थिरता की छाया में अपनी दिशा तलाश रही है, तब भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन उसे एक भरोसेमंद और संभावनाशील शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। 7.8 प्रतिशत की विकास दर निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने यह संदेश दिया है कि वैश्विक संकटों के बीच भी उसकी आर्थिक बुनियाद मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आर्थिक नीतियों और योजनाओं को अब अगले चरण में अधिक रोजगार, अधिक निवेश, अधिक उत्पादन और अधिक समान अवसरों से जोड़ना होगा। भारत के आर्थिक आकाश पर उगता यह उजाला तभी स्थायी प्रकाश बनेगा, जब विकास की रोशनी देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन तक पहुंचे। यही 2047 के विकसित भारत की वास्तविक कसौटी होगी और यही आर्थिक शक्ति को जनशक्ति में बदलने का मार्ग भी।

लेखक – ललित गर्ग
(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

दिल्ली में बनेगा मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों की बार-बार खोदने को समाप्त के लिए मल्टी-यूटिलिटी डक्ट (एमयूडी) विकसित करेगी। इसके तहत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे, ताकि बिजली केबल, पानी और गैस की लाइनों, फायर-हाइड्रेंट नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक यूटिलिटी सेवाओं के लिए इस उपयोग कर सकें। चांदनी चौक में इस पहल को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि मल्टी-यूटिलिटी डक्ट के निर्माण से बार-बार सड़क खोदने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत कम हो जाएगी, यातायात में होने वाली बाधाएं कम होंगी, नागरिकों को होने वाली असुविधा घटेगी और सड़कों की संरचनात्मक मजबूती को भी बेहतर ढंग से बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सरकार ने यह निर्णय हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया।

शास्त्रीय कलाओं से सजी शाम

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। आरके पुरम स्थित तिरुवल्लुवर ऑडिटोरियम के तमिल संगम में अनंत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय शास्त्रीय कलाओं की विविध परंपराओं को एक साझा भावभूमि में पिरोया गया। समन्वय ने अलग-अलग संगीत परंपराओं के मिलन को स्वर दिया, वहीं, गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण से जुड़ी प्रसिद्ध कथा को दशार्या गया। संध्या की समाप्ति पर भार्गवी सुदर्शन ने कहा, कि प्रस्तुति खत्म हो सकती है, पर संगीत चलता रहता है, कथा आगे बढ़ती रहती है और लय निरंतर बहती रहती है। शास्त्रीय संध्या की सूत्रधार प्रख्यात कथक नृत्यांगना भार्गवी सुदर्शन रहीं।

पशु संरक्षण कानूनों पर जागरूकता सत्र करवाया

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस की मध्य जिला पुलिस ने पेटा इंडिया के साथ पशु संरक्षण कानूनों और कानून लागू करने की प्रक्रियाओं पर 60 से अधिक पुलिसकर्मियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया। पेटा इंडिया की कानूनी सलाहकार एवं क्रुएल्टी रिस्पॉन्स की निदेशक मीत अशर ने पशु क्रूरता, अवैध वध, वन्यजीव अपराध और संरक्षित वन्यजीवों को अवैध रूप से रखने से जुड़े मामलों से निपटने के लिए कानूनी मार्गदर्शन दिया। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि सत्र में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने, संबंधित कानूनी प्रावधानों को सही तरीके से लागू करने, जांच, साक्ष्यों के संरक्षण, जब्ती और अभिरक्षा की प्रक्रिया तथा सक्षम प्राधिकारियों और पशु कल्याण संगठनों के साथ समन्वय पर विशेष जोर दिया गया।

स्वामी दयानंद मार्ग जाम से आजाद, 900 मीटर का सफर अब पांच मिनट में

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल स्वामी दयानंद मार्ग (रोड नंबर- 57) पर जाम से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली यातायात पुलिस की पूर्वी रेंज और पीडब्ल्यूडी ने इसे सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। बिहारी कॉलोनी, ईस्ट आजाद नगर और सूर्या अस्पताल के पास बनाए गए यू-टर्न चालू होने तथा अनावश्यक कट बंद होने के बाद करीब 900 मीटर का सफर अब सिर्फ पांच मिनट में तय हो सकेगा। पहले इस दूरी को तय करने में 15 से 20 मिनट लग जाते थे। स्वामी दयानंद मार्ग गांधी नगर, कृष्णा नगर, आजाद नगर, बिहारी कॉलोनी, जगतपुरी और आसपास के घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ता है। अलग-अलग कट और चौराहों के कारण वाहन बार-बार रुकते थे, इस वजह से यहां अक्सर जाम लगता था।

पतंग उड़ाने के विवाद में हुआ झगड़ा, 18 दिन बाद मारा चाकू, हालत नाजुक

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। पतंग उड़ाने के दौरान हुए झगड़े के 18 दिन बाद तीन लोगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित अतुल (35) इस वक्त जीटीबी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसकी हालत नाजुक है। वहीं, पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दो नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी की पहचान नीरज (21) के रूप में हुई है। दोनों नाबालिग 17 साल के हैं। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं।

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि अतुल 16 अगस्त को पतंग उड़ा रहा था। इस बीच उसका नीरज और बाकी दोनों नाबालिगों से झगड़ा हो गया। उस दिन तो किसी तरह बीच-बचाव हो गया, लेकिन आरोपी हमला करने की फिराक में घूमते रहे।

अमित शाह ने साकेत में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को साकेत में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान यहां पौधारोपण भी किया। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, विधायक सतीश उपाध्याय, गजेंद्र यादव और मैक्स अस्पताल के चेयरमैन और एमडी अभय सोय मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए हा कि यह नई स्वास्थ्य सुविधा दिल्ली के चिकित्सा ढांचे को और सुदृढ़ करेगी तथा नागरिकों तक उन्नत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाएगी। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल का उद्घाटन करके दिल्लीवालों को विश्वस्तरीय और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है।

मुख्यमंत्री ने तेहखंड एटीएस का किया उद्घाटन

50 ईवी बसों और दिल्ली-रेवाड़ी ई-बस सेवा को दिखाई झंडी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को तेहखंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) का उद्घाटन किया। इसके साथ-साथ 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्लीझ्ररेवाड़ी अंतरराज्यीय ई-बस सेवा और हसनपुर और गाजीपुर डिपो में दो नए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्लीवासियों को समर्पित किए।

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

मुख्यमंत्री ने इस एटीएस का नवंबर में ही शिलान्यास किया गया था, आज उसका उद्घाटन किया। उन्होंने कुछ ही महीनों में इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग की पूरी टीम और इससे जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साधुवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना ही हमारा संकल्प है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह उपस्थित रहे।

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने तेहखंड डिपो में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, 50 नई इलेक्ट्रिक बसों, दो पब्लिक (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों (हसनपुर एवं गाजीपुर डिपो) तथा दिल्लीझ्ररेवाड़ी अंतरराज्यीय बस सेवा का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि इन नई सुविधाओं से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुरक्षित, सुगम एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी के साथ-साथ दिल्लीवासियों को बेहतर और स्वच्छ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलेगा

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि एटीएस के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 72,000 वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी। इससे फिटनेस जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी सटीकता को बढ़ावा मिलेगा तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। वहीं, ईवी चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार से दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्लीझ्ररेवाड़ी अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से दिल्ली और हरियाणा के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को बेहतर एवं सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलेगा।

बाल यौन शोषण सामग्री मामला

प्रियंक कानूनगो बोले-एमईआईटीवाई और एमआईबी से मांगा जवाब, दिल्ली पुलिस को 15 दिन का समय

बाल यौन शोषण सामग्री के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सख्त रुख पर एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने जवाब दिया है।

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

उन्होंने कहा कि एनएचआरसी ने दो मंत्रालयों (एमईआईटीवाई और एमआईबी) से जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस को भी 15 दिन का समय दिया गया है।

प्रियंक कानूनगो ने कहा, इस मामले में महीने तकरीबन डेढ़ महीने पहले संज्ञान लिया था और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। इस बात समझनी होगी कि अगर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनी है तो निश्चित तौर पर बच्चों का यौन शोषण हुआ है। यह एक अपराध है। दूसरा अपराध बच्चों का यौन शोषण और उनका वीडियो बनाना है। उस वीडियो को ऑनलाइन शेयर करना तीसरा अपराध है। इसी तरह उस सामग्री को बेचने के लिए विज्ञापन चलाना एक अलग अपराध है। उन्होंने कहा, अलग-अलग कई तरीके के अपराध हुए हैं, उनकी पुलिस जांच होती है। इसलिए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जांच करने के निर्देश दिए थे। हमने दिल्ली पुलिस से कहा कि बच्चे देशभर के किस हिस्से के हैं, इसका पता लगाया जाए। दिल्ली को नोटिस इसलिए भेजा गया कि इसमें जो व्हिसलब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन (बीबीसी) है, वो दिल्ली में है। इसलिए आसानी हो। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली पुलिस ने हमें यह जानकारी दी कि उसने मेटा व बीबीसी को नोटिस भेज दिया है और वे काम कर रहे हैं।

इसी बीच, प्रियंक कानूनगो ने कहा, शिकायतकर्ता ने दो सवाल उठाए हैं। उन्होंने हमें बताया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने मेटा को नोटिस जारी किया है। इसलिए, यह कानूनी प्रावधानों के दायरे से बाहर की बात है, क्योंकि अगर कोई अपराध हुआ है तो जांच होगी, नोटिस नहीं भेजा जाएगा। अगर हमें कोई बलात्कारी को नोटिस भेजकर पूछें तो यह तरीका नहीं है। हमें इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए।

डीयू और एएमडी के बीच रणनीतिक साझेदारी, 10 हजार विद्यार्थियों को एआई प्रशिक्षण देने का लक्ष्य

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर नवाचार के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और एएमडी ने रणनीतिक साझेदारी की शुरूआत की। इसके तहत विद्यार्थियों को उद्योग की जरूरत के अनुरूप एआई कौशल प्रदान करने और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दोनों संस्थानों के बीच गुरुवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के बीच सेतु बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में एआई शिक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में एएमडी के साथ डीयू की साझेदारी एक सराहनीय कदम है। एमओयू के तहत एएमडी अपने ह्यएआई एंगेज डेवलपर प्रोग्रामह्ण को दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू करेगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को एएमडी के ओपन-सोर्स आरओसीएम एआई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, सीखने से जुड़े संसाधनों और डेवलपर जीपीयू क्लाउड क्रेडिट्स का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। इस पहल के तहत अगले वर्ष तक करीब 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा का निधन

मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों ने जताया दुख

नई दिल्ली (वेब वार्ता)

दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा का गुरुवार की सुबह सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया है। उन्होंने 23 मार्च 2022 को दिल्ली के लोकायुक्त की शपथ थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली के मंत्रियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कहा कि दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों एवं शुभचिंतकों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति दें। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनका जाना न्याय एवं जनसेवा के क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल दें।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह उनके निधन के समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक बताया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उनके निधन को न्याय जगत एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। सिरसा ने कहा कि न्याय और जनहित के प्रति उनका समर्पण एवं योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर करणी सेना पहुंची हाईकोर्ट, 9 सितंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। करणी सेना ने 6 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदर्शन की तारीख बदलें, तारीख में ऐसा क्या खास है। हाईकोर्ट ने करणी सेना से कहा कि अगर पुलिस किसी तारीख पर अनुमति नहीं दे रही है तो दूसरी तारीख को प्रदर्शन करें। बता दें कि ब्रिक्स समिट में सुरक्षा के चलते दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को सुने बिना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

नियमों को पूरी तरह से वापस लें

प्रदर्शन का मुख्य कारण यूजीसी के नए नियम हैं। प्रदर्शनकारी ह्ययूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026ह्ण के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। करणी सेना और सवर्ण समाज की मांग है कि सरकार इन नए नियमों को पूरी तरह से वापस ले। इसी मांग को लेकर करणी सेना 6 सितंबर को जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। इसी के खिलाफ करणी सेना ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शन की तारीख पहले ही बदली जा चुकी है और यह दूसरी बार है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट अब 9 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि करणी सेना की तरफ से 6 सितंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन और जंतर-मंतर की ओर कूच करने की चेतावनी दी गई है।

करणी सेना मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में स्थित एक क्षत्रिय (राजपूत) संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्षत्रिय समाज के अधिकारों, संस्कृति, इतिहास और हितों का संरक्षण करना तथा समाज को राजनीतिक एवं सामाजिक संगठित करना है।

डीयू कुलपति ने पहले कार्बन गार्डन का किया उद्घाटन, लगाया कल्पवृक्ष का पौधा

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने गुरुवार को वनस्पति विज्ञान विभाग में देश के पहले 'कार्बन गार्डन' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्बन गार्डन में एक कल्प वृक्ष का पौधा भी लगाया। इस कार्बन गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण में अहम योगदान होता है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि गार्डन का क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत ही अच्छी है। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि दुनिया भर में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। भारत में लगभग 17 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की समस्या लोगों के असंतुलित कार्यों से पैदा हुई है, उसका समाधान तकनीक से नहीं किया जा सकता उसके लिए दूसरे कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी को सतत समाधान का प्रयास करना होगा।

एसटीपी घोटाला: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत, 2 लाख रुपये के मुचलके पर मिली राहत

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) दिग्विनय सिंह ने जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें दो लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो श्योरिटी जमा करने की शर्त पर जमानत दी। सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड की एसटीपी परियोजनाओं की

टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जमानत पर सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दलील दी कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब 27 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान जैन को पूछताछ के लिए केवल एक बार बुलाया गया था और दूसरी बार बुलाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैन के वकील ने अदालत से कहा कि मामले से संबंधित सभी सामग्री दस्तावेजी प्रकृति की है और जांच एजेंसियां पहले ही सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सामग्री अपने कब्जे में ले चुकी हैं। ऐसे में आरोपी को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, एसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष दावा किया कि सत्येंद्र जैन आदतन अपराधी हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। इसमें दिल्ली जल बोर्ड की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं के उन्नयन से जुड़े ठेकों में कथित तौर पर टेंडर की शर्तों में हेरफेर, आपराधिक साजिश और संदिग्ध रिश्वत भुगतान के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले 19 अगस्त को अदालत ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। अदालत के गुरुवार के आदेश के बाद अब इस मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है।

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, तीन हमलावरों ने जिम के बाहर मारी गोली

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)

उत्तरी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से सनसनी फैल गई। यह घटना सुबह करीब 7 बजे हुई। हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाई और मौके से भाग गए। इसमें प्रॉपर्टी डीलर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मृतक प्रॉपर्टी डीलर की पहचान 42 वर्षीय प्रमोद कुमार के रूप में हुई है, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के राई के अंतर्गत आने वाले नाहरी गांव के रहने वाले थे। प्रमोद कुमार मुकुल प्रॉपर्टी के संचालक थे और गांव में मुकुल गार्डन के नाम से उनका बैंक्वेट हॉल है। प्रमोद को नरेला के बांकनेर में जिम के बाहर गोली मारी गई। बताया गया कि तीन अज्ञात हमलावरों ने प्रमोद की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के कारण प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसी बीच, स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि, इस हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। इससे पहले, दिल्ली के रोहिणी से बीते दिन लूट और हत्या की घटना सामने आई। मृतक की पहचान करीब 60 साल के राकेश खन्ना के रूप में हुई।

शुरूआती पुलिस जांच में पता चला कि मंगलवार शाम करीब 7.30 बजे तीन लोग घर में घुसे, जबकि चौथा साथी बाहर निगरानी कर रहा था। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर की रेकी की थी। रेकी 30 अगस्त को, यानी घटना से दो दिन पहले की गई थी। घर से करीब 1.5 लाख रुपए कैश और कुछ सोने के गहने लूटे गए थे। जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों की पहचान सिमरन तनेजा, चिराग और पारस के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 23 साल की सिमरन तनेजा, जो मृतक की भतीजी है, इस साजिश की मुख्य आरोपी के रूप में सामने आई।

सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा के वोट मामले पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 03 सितंबर (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सवाल उठाया कि एसआईआर के दौरान आम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जबकि राघव चड्ढा के मतदाता पहचान पत्र को लेकर मीडिया में अनावश्यक रूप से हंगामा किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले आआपा नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पुराने पते पर मतदाता उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका वोट 'शिफ्टेड' दिखाया जाएगा।

संक्षिप्त वार्ता

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह व विधिक अधिकारों पर जागरूकता शिविर आयोजित

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन/प्रभारी सचिव स्मिता गोस्वामी के निर्देशन में जिला चिकित्सालय हरदोई में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

तहसील विधिक सेवा समिति सदर के सचिव/तहसीलदार सचिंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में आयोजित शिविर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कानूनी अधिकार तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता मानसिक रोग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रीतु खरे ने की। उन्होंने मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जिला चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। लीगल एड क्लीनिक कीर्ति कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक से सात सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संतुलित आहार, पोषक तत्वों और कुपोषण से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

साल के बारह महीनों चुनावी मोड में रहने वाली डबल इंजन सरकार में जनता के मुद्दे कहीं गुम

वेब वार्ता, अमरोहा

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही एकमात्र दल है जो युवाओं और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश सह प्रभारी संजीव आर्या ने आगे कहा कि जिस सरकार की पहचान केवल पेपर लीक और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति और येन-केन प्रकरेण चुनाव जीतने तक सीमित हो गई हो, उससे युवाओं के बेहतर भविष्य की उम्मीद रखना बेमानी है।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा मे एक दिवसीय संवाद बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश सह-प्रभारी संजीव आर्या ने सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला बोला। बैठक में संजीव आर्या ने कहा कि जिस सरकार की पहचान केवल पेपर लीक और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति तक सीमित हो गई हो, उससे युवाओं के बेहतर भविष्य की उम्मीद रखना बेमानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान, मजदूर और युवा वर्ग की अनदेखी कर सरकार चंदा जुटाने और विवादों में उलझी है, जिससे जनता की मूल समस्याएं पीछे छूट गई हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही एकमात्र दल है जो युवाओं और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ रही है।

अयोध्या और वाराणसी से आनंद विहार के बीच चलेंगी दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

वेब वार्ता, मुरादाबाद

रेल प्रशासन ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दो जोड़ी आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बुधवार को बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल और वाराणसी-आनंद विहार टर्मिनल के बीच इन ट्रेनों का संचालन एक-एक फेरे के लिए किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04213 अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस 3 सितंबर को अयोध्या कैंट से शाम 18:20 बजे रवाना होकर बाराबंकी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद में ठहराव लेते हुए अगले दिन सुबह 06:10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। मुरादाबाद में यह ट्रेन रात 02:42 बजे पहुंचकर 02:50 बजे रवाना होगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04214 आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या कैंट स्पेशल 4 सितंबर को सुबह 08:20 बजे चलकर गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और बाराबंकी होते हुए रात 21:35 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। यह गाड़ी मुरादाबाद में सुबह 11:35 बजे पहुंचकर 11:45 बजे प्रस्थान करेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी यात्रियों से भरी बस,10 घायल

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। गंगा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में बस सवार करीब 10 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

जानकारी के अनुसार बस लुधियाना से उन्नाव जिले के बांगरमऊ जा रही थी। बस में करीब 60 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 286 के पास अचानक बस अनियंत्रित हो गई। चालक जब तक बस को संभाल पाता, तब तक बस सड़क किनारे पलट गई। हादसा होते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हादसे में घायल करीब 10 यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवायजपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल घायलों की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

हादसे के बाद बस का चालक और परिचालक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जांच में बस के अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आई है, हालांकि बस किस वजह से अनियंत्रित हुई, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है।

ली जा रही है जानकारी

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं। यात्रियों से भी दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसे के समय बस की रफ्तार कितनी थी और चालक का नियंत्रण किस वजह से बिगड़ा।

सामान्य कराई यातायात व्यवस्था

दुर्घटना के बाद कुछ समय तक एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए यातायात व्यवस्था सामान्य कराई। हादसे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

खराब प्रगति पर तीन बीडीओ को नोटिस, सीडीओ ने समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 03 सितम्बर। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में खराब प्रगति मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल ने हरपालपुर, संडीला और भरखनी के खंड विकास अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सुधार करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में फैमिली आईडी, मनरेगा, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, एनआरएलएम समेत विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। मनरेगा में मानव दिवस सृजन, अपूर्ण कार्यों, जीआईएस मॉनिटरिंग और एनएमएमएस की प्रगति की जानकारी ली गई। साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति भी जानी गई। सीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 14,871 और मुख्यमंत्री आवास योजना के 2,338 आवासों का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास के पात्र लाभार्थियों का चयन कर प्रस्ताव शीघ्र भेजने तथा मुख्यमंत्री आवास के पात्र लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी करने को कहा।

कार्यवाहक एआरटीओ ने संभाला प्रशासन का कार्यभार

वेब वार्ता, कानपुर। शासन की बड़ी कार्यवाही के बाद एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह और एआरटीओ प्रवर्तन तृतीय दल सोमलता यादव को बुधवार को निलंबित कर दिया गया था। गुरुवार को एआरटीओ प्रवर्तन कहकशा खातून को कार्यवाहक एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करते ही विभाग के सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसी भी आवेदक को कार्यालय के चक्कर नहीं लगवाए जाएंगे। जोभी कार्य होगा उसके आवेदक को पूरी जानकारी देते हुए काम पूरा होने पर उन्हें दूरभाष द्वारा सूचित करेंगे जिससे उनका समय बचेगा और विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

बीते 24 अगस्त को पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यवाही ने अपना असर दिखाया और विभाग की कारगुजारियों की रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी गई। शासन ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए एआरटीओ प्रशासन व प्रवर्तन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस बड़ी कार्यवाही से विभाग में आफरा तफरी के साथ ही हड़कम मचा हुआ है। बाबू कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर काम कर रहे है ताकि किसी बाहरी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो सके। इस पूरे मामले को लेकर पूरे आरटीओ विभाग में सन्नाटा पसरा हुआ है। सारथी भवन के साथ प्रशासनिक कार्यालय में भी इक्का दुक्का आवेदक ही दिखाई पड़े।

आवेदकों की समस्या का जल्द किया जाएगा समाधान का दावा

कानपुर मंडल आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने आवेदकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने दावा किया है। इसके लिए उन्होंने कार्यवाहक एआरटीओ प्रशासन कहकशा खातून को निर्देशित किया कि एक बाबू को नियुक्त किया जाए और उन्हें एक आगंतुक रजिस्टर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्टर में आवेदक की समस्या, उनका नाम,पता और मोबाइल नंबर दर्ज कर उन्हें निश्चित समयावधि में कार्य कर उन्हें दूरभाष से सूचित किया जाए ताकि आवेदकों को विभाग के चक्कर न लगाना पड़े। हालांकि पूर्व में हेल्प डेस्क बनाया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात जस के तस हो गए थे। अब नया निर्देश किया प्रभावी होगा ये आने वाले कुछ दिनों में जमीनी स्तर पर पता चल जायेगा।

एटीएस सेंटर की भी होनी चाहिए जांच

जब से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस एटीएस (ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन) निजी हाथों में गई है। तब से उनकी पौ बारह हो गई है। सूत्रों के अनुसार एटीएस फिटनेस सेंटर पर वाहन स्वामियों से सरकारी फीस के अलावा 5000 से 9000 तक की अवैध वसूली दलालों और फिटनेस सेंटर के कर्मचारियों द्वारा सांठगांठ कर धड़ल्ले से की जा रही है। इसे साथ ही गाड़ी धुलाई और रेडियम का अतिरिक्त पैसा भी लिया जा रहा है। अगर सेंटर की जांच की जाए तो काफी बड़ा खेल का खुलासा हो सकता है कि तरह से निजी कंपनी दलालो से सांठगांठ कर उगाही में लगी हुई है।

तुलसीदास का समन्वयवादी साहित्य आज भी प्रासंगिक

राष्ट्रीय संगोष्ठी में विद्वानों ने रखे विचार

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, अल्लीपुर, हरदोई एवं अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या (संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश) के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय परिसर में समन्वय के कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाधर्मिता विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, साहित्यकारों, चिंतकों, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं गोस्वामी तुलसीदास के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। उदय वीर सिंह उदय ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्रस्तावना रखते हुए डॉ. देवी प्रसाद तिवारी ने कहा कि तुलसीदास ने ज्ञान, भक्ति और कर्म के साथ समाज के विभिन्न वर्गों एवं विचारधाराओं को समन्वय के सूत्र में पिरोने का कार्य किया।

मुख्य अतिथि प्रो. अवनीश अवस्थी, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि तुलसीदास का समन्वय केवल शैव-वैष्णव परंपराओं तक सीमित नहीं था, बल्कि भाषा, समाज, संस्कृति और दर्शन के स्तर पर भी व्यापक था। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन का अनुपम महाकाव्य है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मुख्य वक्ता श्री राज किशोर, प्रांत प्रमुख सामाजिक समरसता, अवध प्रांत ने कहा कि तुलसीदास ने विषमताओं से भरे समाज को एकजुट करने का कार्य किया। रामचरितमानस में राम का चरित्र सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ उदाहरण है। विशिष्ट अतिथि ज्ञान प्रकाश आकुल एवं श्री प्रख्यात ने काव्य पाठ प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश ने कहा कि तुलसी का साहित्य लोक कल्याण और सामाजिक समरसता की भावना से अनुप्राणित है। ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित

कार्यक्रम के दूसरे चरण में महाविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी एवं बीएड के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनपद के वरिष्ठ साहित्यकारों एवं पत्रकारों डॉ. नरेश चंद्र शुक्ला, डॉ. बीएस पांडे, डॉ. ईश्वर चंद्र वर्मा, देश दीपक शुक्ला, अजित्यानंद मणि, डॉ. शीला पांडेय, डॉ. राहुल सिंह, महेश मिश्र, वेद प्रकाश अवस्थी सहित अन्य को अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शीर्षेन्दु शील त्रिवेदी ह्यविपिनह्न ने किया। संचालन श्री राजकुमार सिंह प्रखर ने किया। अंत में डॉ. देश दीपक शुक्ला ने अतिथियों, विद्वानों, वक्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी का समापन राष्ट्रगान एवं जलपान के साथ हुआ।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर ने जीता 39वीं यूजी पीडियाट्रिक क्विज का खिताब, झांसी की टीम रही उपविजेता

4 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों के बीच हुआ कड़ा मुकाबला : 150 से अधिक छात्र-छात्राओं ने की सहभागिता

कुल 6 राउंड आयोजित किए गए। क्विज को अत्यंत ज्ञानवर्धक और रोचक बनाने के लिए सामान्य प्रश्नोत्तर राउंड, विजुअल राउंड तथा रैपिड फायर राउंड सम्मिलित रहे। इस अवसर पर मेडिकल छात्रों में बाल रोग विज्ञान के प्रति रुचि व समझ बढ़ाने की दिशा में इस क्विज को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया।

प्रतियोगिता के दौरान लगभग 150 रेजिडेंट छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतियोगिता में सभी टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। प्रतियोगिता में अंकों के आधार पर विजेताओ का निर्णय किया गया जिसमें प्रथम स्थान जी एस वी एम मेडिकल कानपुर से डॉ शिवांगी चंद्रा, डॉ अवंतिका सिंह, एम ल बी झांसी मेडिकल से डॉ आयुष अग्रवाल, डॉ आलोक प्रजापति को द्वितीय स्थान मिला।

हमारे ज्ञान को और जानकारी प्रदान करती है

कार्यक्रम के अंत में डॉ ए के आर्या, डॉ शैलेन्द्र गौतम डॉ यशवंत राव, डॉ अमितेश यादव ने सभी प्रतिभागी टीमों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए तथा विजेता व उपविजेता टीमों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉ संजय काला ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा इस तरह की प्रतियोगिता हमारे ज्ञान को और जानकारी प्रदान करती है।

हमारा गांव-हमारा सवाल यात्रा यादव बाजार, कौड़िया, मुडियार होते हुए गोलवा पहुंची

निजामाबाद। भारी बारिश में निजामाबाद की जर्जर, कीचड़ भरी सड़कों से होती हुई विश्राम राय और राम बचन यादव स्मृति यात्रा निजामाबाद क्षेत्र से देर शाम नौहरा गोलवा पहुंची। यात्रियों ने मेजवा पहुंचकर कैफ़ी आज़मी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। हमारा गांव, हमारा सवाल पदयात्रा तीसरे दिन निजामाबाद के यादव बाजार से शुरू होकर कौड़िया, मुंडियार की टूटी-फूटी सड़कों, कीचड़ भरे रास्तों से होती हुई सोशलिस्ट नेता रामवचन यादव के गांव नौहरा गोलवा पहुंची। रास्ते में कौड़िया, मुड़ियार, फूलपुर, अंबारी में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हुआ।

नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए किसान नेता राजीव यादव ने कहा कि निजामाबाद से लहीडीह, कौड़िया, मुडियार होते हुए बेलवाई तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव था उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने शासन को चौड़ीकरण का प्रस्ताव भेजा था लेकिन चौड़ीकरण के प्रस्ताव को नवीनीकरण में बदल दिया गया।

बारिश के पहले सड़क बनवाने के आश्वासन के साथ विभाग ने बताया था कि नवीनीकरण के लिए 13 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। भदुली-निजामाबाद, निजामाबाद-रानी की सराय समेत निजामाबाद की जर्जर सड़कों को बनवाने के लिए सड़कों पर जनता को उतरना होगा।

पूर्वांचल किसान यूनियन महासचिव वीरेंद्र यादव ने कहा कि आज के दौर में राम बचन यादव के विचार इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि रामबचन यादव के साथियों ने भी जमीनों के सवाल, सड़कों का सवाल, नहरो के सवाल को जनता का सवाल बनाया था। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी थी। रामबचन यादव के विचारों को आत्मसात करते हुए जन संघर्षों की लड़ाई लड़ी जाएगी।

बिहार से चलकर आए समाजवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी जमुना प्रसाद सिंह के पौत्र जयप्रकाश सिंह ने कहां की उत्तर प्रदेश और बिहार समाजवादी राजनीति केंद्र रहा है।

आज मैं बिहार से चलकर बाबा रामबचन यादव की धरती को नमन करने आया हूं। हम अपने पुरखों की विरासत से प्रेरणा लेते हुए समाजवादी विचारधारा को मजबूत करेंगे। यात्रा में प्रमुख रूप से गुड्डू, मनोज यादव, साहबदीन, अधिवक्ता विनोद यादव, दुर्गा यादव, राजेंद्र यादव, राजकुमार सिंह, संतोष कुमार धरकार, धनंजय शुक्ला, एडवोकेट अशोक कुमार, नंदलाल यादव, मनोज यादव, अवधेश यादव, प्रेम, सत्यम प्रजापति, महेंद्र यादव, दिनेश मास्टर, श्याम सुंदर मौर्य सहित दर्जनों लोग शामिल रहे।

म धूमधाम से मना जन्माष्टमी पर्व

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस दौरान नन्हे-मुन्ने छात्र-छात्राएं राधा-कृष्ण, ग्वाल-बाल सहित विभिन्न धार्मिक पात्रों की मनमोहक वेशभूषा में पहुंचे। भगवान श्रीकृष्ण की आकर्षक झांकी ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी, रासलीला और कृष्ण जन्म पर आधारित प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरीं। भजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से विद्यालय परिसर भक्तिमय हो उठा।

बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, आदर्शों और कर्मयोग के संदेश से परिचित कराया गया। विद्यालय प्रबंधक मुकेश सिंह ने कहा कि भारतीय पर्व-त्योहार हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान हैं। ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रधानाचार्या भूमिका सिंह ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा को निखारने का बेहतर माध्यम हैं।

कार्यक्रम में लक्ष्मी देवी, कोमल यादव, कविता गुप्ता, विनीता त्रिवेदी, सोनम शुक्ला, शैलजा मिश्रा, मंशा वाजपेई, प्रज्ञा द्विवेदी, सोनी शुक्ला, पूजा चौहान, आकांक्षा गुप्ता, प्रतीक्षा पांडे, राखी गुप्ता, पूजा चन्देल, कल्पना, रूबी कश्यप, परी गुप्ता, शिवांगी गुप्ता, राम प्रकाश पाण्डेय, अशोक गुप्ता, अभिनव सिंह, संजय कुमार, आयुष यादव सहित समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहा।

मे को लेकर विवाद, पति ने पत्नी ंसी राइफल से मारी गोली

हरदोई। शाहाबाद थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव में जमीन के बैनामे को लेकर पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद गुरुवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान पति दुर्गाप्रसाद ने अपनी पत्नी दुर्गावती (करीब 45 वर्ष) को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। गोली पेट में लगने से महिला गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में गिर पड़ी।

घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई। परिजन आनन-फानन घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर शाहाबाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी शस्त्र तथा विवाद के कारणों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी शाहाबाद आलोक राज नारायण ने बताया कि 3 सितंबर 2026 को शाहाबाद थाने पर महिला को उसके पति द्वारा घरेलू विवाद के चलते लाइसेंसी शस्त्र से गोली मारकर घायल किए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में मजबूत हो रहा सड़क नेटवर्क

- भोपाल। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को व्यापक और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, फोरलेन मार्ग और रिंग रोड के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरों को देश के बड़े आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य बेहतर आवागमन के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि वाराणसी-विशाखापट्टनम कॉरिडोर के प्रथम चरण में वाराणसी से नागपुर तक कनेक्टिविटी विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में जबलपुर-रीवा से लेकर उत्तरप्रदेश सीमा तक और दक्षिण में नागपुर तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में सीमेंट-विहीन कंक्रीट की सड़कों के लिए सीएसआईआर-एम्प्री के साथ होगा एमओयू

- भोपाल। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने बुधवार को सीएसआईआर-एम्प्री, भोपाल का भ्रमण किया। उन्होंने संस्थान में अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकसित आधुनिक तकनीकों एवं नवीन निर्माण सामग्रियों का अवलोकन किया तथा उनकी उपयोगिता एवं तकनीकी विशेषताओं की जानकारी ली। मंत्री श्री सिंह ने लोक निर्माण विभाग की सड़क, पुल एवं भवन निर्माण परियोजनाओं में स्वदेशी, पर्यावरण-अनुकूल, टिकाऊ एवं लागत-किफायती निर्माण तकनीकों के उपयोग की संभावनाओं का परीक्षण कर इन्हें व्यावहारिक रूप से अपनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

'गरुड़' ने 52000 छुपी हुई संपत्तियां ढूंढकर बढ़ाया नगरीय निकायों का राजस्व

बाढ़ आने से पहले कर देगा अलर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जीआईएस तकनीक पर आधारित 'गरुड़' प्लेटफॉर्म को ई-नगर पालिका और अन्य संबंधित विभागों के साथ एकीकृत किया है। इस डिजिटल व्यवस्था से एक तरफ जहां राज्य के निकायों के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, वहीं आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी भी बेहद आसान हो गई है।

52 हजार से अधिक अचिन्हित संपत्तियों की पहचान

सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों और जीआईएस डेटा के मिलान से प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में 52,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियों को खोजा गया जो अब तक कर-दायरे से बाहर थीं। इससे निकायों के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

क्लाउड-आधारित गरुड़ प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 'अचीवमेंट इन जीआईएस अवॉर्ड' से नवाजा है।

'फ्लड सिमुलेशन' से बाढ़ पूर्व चेतावनी

गरुड़ प्रणाली में शामिल यह विशेष मॉड्यूल कंप्यूटर पर यह सटीक आकलन करता है कि अत्यधिक वर्षा या नदियों के उफान पर होने पर शहर के किन-किन हिस्सों में पानी भर सकता है। इससे समय रहते राहत व बचाव कार्य की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार की उन्नत तकनीक अपनाने वाला मप्र देश का पहला राज्य है। वर्तमान में नर्मदापुरम जिले में इसका सफल परीक्षण जारी है।

अतिक्रमण और नेटवर्क की डिजिटल मैपिंग

इस सिस्टम के जरिए 277 निकायों के पेयजल आपूर्ति और 46 निकायों के सीवरेज नेटवर्क का डिजिटल मानचित्र तैयार किया गया है। इसके जरिए जल व सीवेज पाइपलाइनों के आपस में मिलने (ओवरलैप) के खतरों को समय रहते पहचाना जा रहा है। गरुड़ सिस्टम के माध्यम से एयरपोर्ट क्षेत्र में इमारतों की ऊंचाई, मास्टर प्लान के उल्लंघन, ऐतिहासिक स्थलों (हेरिटेज जोन) और अतिक्रमण पर भी लगातार नजर रखी जा रही है।

1.15 लाख शिक्षक पद खाली, फिर भी नौकरी के लिए भूख हड़ताल

भोपाल। राजधानी भोपाल में शिक्षक भर्ती का मुद्दा अब एक बड़े और निर्णायक आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदेश में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के अभ्यर्थी एक साथ एकजुट होकर नीलम पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन युवाओं का सीधा आरोप है कि सरकार ने पात्रता और चयन परीक्षा के कड़े मापदंड तय किए, लेकिन परीक्षा पास करने के बावजूद पदों की संख्या इतनी कम है कि उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है।

तबीयत बिगड़ने पर भी अनशन तोड़ने से इनकार

आंदोलन के दौरान हालात अब गंभीर होते जा रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठीं वर्ग-2 की एक अभ्यर्थी प्रियंका सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई। मंगलवार को उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, वे अपना अनशन नहीं तोड़ेंगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 31 अगस्त से इस धरने ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

1.15 लाख शिक्षकों की कमी, फिर भी पद सीमित क्यों?

धरने में शामिल अभ्यर्थी लेखा दास ने बताया कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1.15 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, फिर भी सरकार नाममात्र के पदों पर भर्ती कर रही है। साल 2024 में पात्रता और 2025 में चयन परीक्षा आयोजित की गई थी।

इसमें सामान्य वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स 50% और आरक्षित वर्ग (ओबीसी, एससी, एसटी) के लिए 40% तय किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि दीप्ति राय (99.60%), ममता गौतम (99.06%) और श्रेष्ठ जोशी (99.047%) जैसे टॉपर अभ्यर्थियों को भी ऊंचे अंक लाने के बावजूद पदों की कमी का हवाला देकर नौकरी से वंचित रखा जा रहा है।

ये हैं प्रदर्शनकारियों की दो प्रमुख मांगें

आंदोलन कर रहे युवाओं (जिसमें लगभग 15 हजार अभ्यर्थी वर्ग-2 और इतने ही वर्ग-3 के बताए जा रहे हैं) ने सरकार के सामने मुख्य रूप से दो सूत्रीय मांगें रखी हैं:

वर्ग-2: इस वर्ग के तहत हर विषय में कम से कम 3-3 हजार पदों की वृद्धि की जाए।

वर्ग-3: इस वर्ग के अंतर्गत कुल 25 हजार पदों पर नियुक्ति दी जाए।

अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि सरकार का रवैया विरोधाभासी है। एक तरफ शासन खुद स्वीकार कर रहा है कि स्कूलों में शिक्षकों का टोटा है, वहीं दूसरी तरफ सभी योग्यताएं पूरी करने वाले होनहार युवाओं को पदों की कमी बताकर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी नाइंसाफी ने अभ्यर्थियों को भूख हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है।

साइबर ठगों को सिम बेचने वाला गिरफ्तार

200 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में देता था

इंदौर। एमआईजी थाना पुलिस ने साइबर ठगी के लिए फर्जी सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क का राजफाश किया है। आपरेशन फास्ट-2.0 के तहत हुई जांच में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। ठगों ने महज 200 रुपये में सिमकार्ड खरीदकर 500 रुपये में आगे बेच दिया। इसके बाद यह सिमकार्ड साइबर ठगों तक पहुंचा। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है जबकि तीन आरोपित फरार है।

एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, जांच आइ4सी (इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर) गृह मंत्रालय से मिले डाटा के आधार पर शुरू हुई थी। इंदौर नगरीय क्षेत्र में 49 संदिग्ध

पीओएस (बिक्री का स्थान) धारकों और सिम विक्रय एजेंटों से जुड़ी 151 संदिग्ध सिमकार्ड की जानकारी मिली थी। इन सिमकार्ड का इस्तेमाल देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 212 वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों में पाया गया।

पुलिस ने संबंधित पीओएस कोड के सिमकार्ड विक्रेता रोहित दलवे से पूछताछ की। उसने बताया कि उसने 15 मार्च 2026 को दस्तावेजों का मिलान कर राजेश चौधरी के नाम पर सिमकार्ड जारी किया था। राजेश ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने आधार कार्ड पर सिमकार्ड लिया था। बाद में 200 रुपये लेकर भगवानदास उर्फ नाना को दे दी। भगवानदास ने 500 रुपये में हिमांशु जुनवाल को बेच दी और हिमांशु ने यह सिमकार्ड आशीष शर्मा को दिया। जांच में पता चला कि इसी सिमकार्ड का इस्तेमाल आशीष ने साइबर ठगी के लिए किया। आरोपित लोगों को कम कीमत पर जींस-पैंट उपलब्ध कराने और फ्रेंचाइजी देने का झांसा देते थे। रुपये लेने के बाद सामान नहीं देते थे।

उत्तर प्रदेश के खीरी जिले के अनिल कुमार गुप्ता से भी इसी तरह संपर्क किया गया। उन्हें झांसा देकर 10 हजार रुपये ले लिए गए। अनिल ने 27 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भगवानदास उर्फ नाना, हिमांशु उर्फ रोहित जुनवाल और आशीष की तलाश जारी है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से आरंभ होगा सेवा-संकल्प अभियान

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष केवल सत्ता के नहीं बल्कि निरंतर सेवा और राष्ट्र निर्माण के 25 वर्ष हैं। सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई यह संवैधानिक यात्रा आज एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंची है। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक उन्होंने जन सेवा को अपना ध्येय माना और आज भी संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के विकास और लोकतंत्र को सशक्त करने में अविस्मरणीय योगदान दिया है। इस गौरवपूर्ण यात्रा को जन-जन तक पंहुचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, एक माह तक सेवा-संकल्प अभियान चलाया जाएगा।

जीआईएस आधारित नवाचार के लिए मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अचीवमेंट इन जीआईएस अवार्ड

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश नगरीय विकास, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक तकनीकों के समन्वय से प्रशासनिक दक्षता के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। इसी श्रृंखला में राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विकसित एकीकृत जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म 'गरुड़' (जीआईएस आधारित अर्बन डेटा एनालिटिक्स सेंटर) के उत्कृष्ट और नवोन्मेषी उपयोग के लिए मध्यप्रदेश को प्रतिष्ठित ह्यअचीवमेंट इन जीआईएस अवार्डह्न से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह में एसरी इंडिया निदेशक श्री अजेन्द्र कुमार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त श्री संकेत भोंडवे को यह सम्मान प्रदान किया।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप राज्य में तकनीक-आधारित सुशासन और पारदर्शी नगरीय प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे ठोस प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 'गरुड़' के माध्यम से डेटा को निर्णय लेने का मुख्य आधार बनाया गया है, जिससे नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सेवा वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार आ रहा है। 'गरुड़' एक अत्याधुनिक एकीकृत जीआईएस आधारित डेटा एनालिटिक्स सेंटर है, जो नगरीय निकायों के विभिन्न शहरी और राजस्व संबंधी आंकड़ों को एक मंच पर लाकर उनका स्थानिक विश्लेषण करता है। इस डिजिटल नवाचार के माध्यम से राज्य के नगरीय निकायों में संपत्ति एवं राजस्व का मानचित्र-आधारित विश्लेषण, अपंजीकृत तथा संभावित नई संपत्तियों की सटीक पहचान और राजस्व संवर्धन के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही, जलापूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क, भूमि उपयोग, अतिक्रमण नियंत्रण, भवन अनुज्ञा और नगरीय अधोसंरचना की रियल-टाइम डिजिटल निगरानी को अत्यंत सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया गया है।

अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी उपलब्ध होगी बिजली : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सतत रूप से सुविधाएं देने का कार्य किया जा रहा है। अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे वे दिन के समय में भी अपनी फसलों में पानी दे सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषि उपज मंडी परिसर श्योपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान मेले को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने श्योपुर के किसानों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि उपज मंडी श्योपुर में किसानों के लिए नवीन विश्राम गृह निर्माण के लिये 60 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। ग्वालियर एयरपोर्ट से कार्यक्रम में श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामनिवास रावत औरअपेक्स बैंक अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह यादव भी वर्चुअली उपस्थित थे।

परीक्षा परिणाम आने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या में नहीं किया जा सकता परिवर्तन

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापित पदों की संख्या परीक्षा परिणाम आने के बाद बढ़ाने-घटाने, बैकलॉग पदों पर भर्ती आदि विषयों पर वैधानिक प्रावधानों अनुसार स्थिति स्पष्ट की है। अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक वर्ग 1 (उच्च माध्यमिक शिक्षक), वर्ग 2 (माध्यमिक शिक्षक) एवं वर्ग 3 (प्राथमिक शिक्षक) की भर्ती में विज्ञापित पदों में वृद्धि की मांग लगातार की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों द्वारा पदवृद्धि की मांग के संबंध विभाग द्वारा वस्तुस्थिति बताई गई है। इसके अनुसार किसी भी विज्ञापन में विज्ञापित पदों की संख्या को परीक्षा परिणाम आ जाने के बाद बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है।

तीन साल बाद खुला रास्ता, इंदौर नगर निगम में अब बाहरी क्षेत्रों के नक्शे भी होंगे पास

इंदौर। वर्षों से भवन निर्माण की अनुमति के इंतजार में अटके शहर के मध्य क्षेत्र के बाहर के हजारों रहवासियों को बड़ी राहत मिली है। अब नगर निगम छावनी, परदेशीपुरा, कुलकर्णी नगर सहित शहर के पूर्व विकसित बाहरी क्षेत्रों में 5000 वर्गफीट तक के भूखंडों पर भवन निर्माण और पुनर्निर्माण के नक्शे मंजूर कर सकेगा। इसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

वर्ष 2023 से पहले इन क्षेत्रों में डाटा फार्म के माध्यम से नक्शे मंजूर किए जाते थे, लेकिन बाद में यह व्यवस्था बंद कर दी गई। इसके चलते पिछले तीन वर्षों से इन क्षेत्रों के रहवासी भवन निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति के लिए परेशान हो रहे थे।

नगरीय प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम में संशोधन कर नगर निगम को 5000 वर्गफीट तक के भूखंडों पर भवन निर्माण एवं पुनर्निर्माण की अनुमति देने के अधिकार दिए हैं। यह व्यवस्था इंदौर सहित प्रदेश के अन्य शहरों के पूर्व विकसित क्षेत्रों में भी लागू होगी।

मप्र भूमि विकास नियम में किया संशोधन

अब तक पुरानी कॉलोनियों, गांव, बस्ती, टोला और माजरा आदि क्षेत्रों में टीएंडसीपी के पास अभिलेख, नक्शे या लेआउट उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन निर्माण और पुनर्निर्माण की अनुमति लेने में लोगों को कठिनाइयों का सामना

करना पड़ता था। वर्ष 2023 से पहले शासन ने डाटा फार्म के माध्यम से नगर निगम को ऐसे क्षेत्रों के नक्शे मंजूर करने का अधिकार दिया था। बाद में यह व्यवस्था बंद कर दी गई। इसके बाद इन क्षेत्रों में नक्शे मंजूर नहीं हो पा रहे थे और कई जगह बिना अनुमति निर्माण की स्थिति बन रही थी।

इन क्षेत्रों के रहवासियों को मिलेगी राहत

कुम्हारखाड़ी, गाड़राखेड़ी, बाणगंगा, भागीरथपुरा (ओल्ड), परदेशीपुरा, रेसकोर्स रोड, न्यू देवास रोड, वायएन रोड, छोटी खजरानी, दुबे का बगीचा, विनोबा नगर, मुराई मोहल्ला (संयोगितागंज), उषागंज (छावनी), श्रद्धानंद मार्ग, कलाली मोहल्ला, किबे कंपाउंड, साउथ तुकोगंज, एमजी रोड, आरएनटी मार्ग, छोटी ग्वालटोली, मनोरमागंज गली नंबर छह, नवरतन बाग, बड़ी ग्वालटोली, कुमावतपुरा, बारामत्था, हाथीपाला, मुराई मोहल्ला (जूनी इंदौर), मालीपुरा, बीके सिंधी कॉलोनी, माडल टाउन, जबरन कालोनी, गाड़ी अड्डा (जूनी इंदौर), पारसी मोहल्ला और चितावद सहित अन्य क्षेत्रों के रहवासियों को इसका लाभ मिलेगा।

मास्टर प्लान की सड़कों से जुड़े क्षेत्रों को भी राहत

छावनी सहित शहर के कई क्षेत्रों में मास्टर प्लान की सड़कों का काम चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए सैकड़ों मकान तोड़े जा चुके हैं। इन मकानों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि संबंधित क्षेत्रों में नगर निगम से नक्शे मंजूर नहीं हो रहे थे। इसके चलते कई लोग मजबूरी में बिना नक्शा मंजूर कराए निर्माण कर रहे थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे लोग नियमानुसार नक्शा मंजूर कराकर भवन का निर्माण कर सकेंगे।

लिफ्ट में छूटा आठ लाख रुपये से भरा बैग, घर पहुंचने से पहले ही चोर ले उड़ा; इंदौर पुलिस ने खोज निकाला

इंदौर। बैंक से लोन के आठ लाख रुपये लेकर घर पहुंचे व्यक्ति ने रुपयों से भरा बैग लिफ्ट में रखा और घर पहुंचने की जल्दबाजी में उसे वहीं भूल गया। कुछ देर बाद जब बैग लेने वापस पहुंचा तो वह गायब था।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपित गिरफ्तार कर रुपये बरामद कर लिए। घटना ट्रेजर फैंटेसी कालोनी की है। फरियादी बैंक से लोन की राशि लेकर अपने घर पहुंचा था। लिफ्ट में रुपयों से भरा बैग फर्श पर रखने के बाद बाहर निकल गया, लेकिन बैग उठाना भूल गया। कुछ देर बाद ध्यान आया तो लिफ्ट में पहुंचा, लेकिन तब तक बैग गायब हो चुका था।

फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली और फुटेज के आधार पर आरोपित यमन जैन निवासी आनंद नगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से आठ लाख रुपये की पूरी रकम बरामद कर ली।

टैक्सी में छूटे डेढ़ लाख के दो मोबाइल, पुलिस ने 30 मिनट में खोजे

एक युवती के डेढ़ लाख रुपये कीमती दो मोबाइल टैक्सी में छूट गए। युवती की फ्लाइट का वक्त हो चुका था। पुलिस ने 30 मिनट में फोन ढूंढ कर लौटा दिए। घटना मंगलवार की शाम करीब सात बजे एयरपोर्ट की है। कोलकाता जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की महिला यात्री ने सउनि ओमसत्य यादव और एरोड्रम थाने के आरक्षक प्रताप सिंह कौरव को बताया कि वह करीब 10 मिनट पहले ओंकारेश्वर से टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंची थी। जल्दबाजी में उसके दोनों मोबाइल टैक्सी में ही छूट गए। महिला की फ्लाइट रात 8.30 बजे रवाना होनी थी। पुलिसकर्मियों ने एयरपोर्ट और आसपास के फुटेज खंगाले और टैक्सी (एमपी 09 बीयू 7278) को ढूंढ लिया। पुलिस ने पीओएस की मदद से वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर निकाला और युवती के फोन भी मिल गए।

भगवान श्रीकृष्ण के जहां-जहां चरण पड़े, उन्हें श्रीकृष्ण तीर्थ के रूप में विकसित कर रही राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन कभी आसान नहीं रहा, जिन्हें जन्म लेते ही मार डालने का प्रयास किया गया हो, ऐसे शिशु का कान्हा से विश्व को श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान देने वाले श्रीकृष्ण वंदे जगतगुरु की उपाधि पाने तक का जीवन बेहद संघर्षमय और कठिन परिस्थितियों में बीता। निराशा की घनघोर परछाइयों के बावजूद उन्होंने चुनौतियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और अपने जीवन लोक कल्याण के लिये का सदुपयोग किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने कभी मोह नही रखा। जीवन में जिस व्यक्ति विशेष और वस्तु से उनका सामना हुआ, एक बार वहां से लौटने के बाद दोबारा वे किसी से नहीं मिले। सर्वविदित है कि विश्व के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान भी योगीराज भगवान श्रीकृष्ण के मुखारविंद से ही निकला। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण 64 कलाओं, 14 विद्या और 18 पुराणों में निष्णात थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार की शाम रविन्द्र भवन में आयोजित भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं पर केन्द्रित रासलीला समारोह में उपस्थित दर्शकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां राधा-कृष्ण की सजीव झांकी में राधा-कृष्ण बने सुधि और सुघढ़ कलाकारों की विशेष आरती उतारी और उनसे आशीष पाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रासलीला समारोह में दूरदराज से आए कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा सभी को हलषष्ठी और जन्माष्टमी की अग्रिम बधाई दी।

रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन

कहा- 'नक्सलवाद और भय से मुक्त होकर प्रगति व संभावनाओं की नई राह पर छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद, भय और अभाव के दौर से निकलकर शांति, प्रगति और अवसरों की ओर बढ़ रहा है। कभी हिंसा के लिए पहचाने जाने वाले इलाकों में अब सड़क, स्कूल, अस्पताल, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश पहुंच रहा है। यह बात उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रायपुर एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। इतिहास

उपराष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी हिंसा और भय का माहौल था, वहां विकास की गतिविधियां पहुंच रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कनेक्टिविटी और निवेश का विस्तार भी हो रहा है।

एम्स रायपुर की उपलब्धियों की सराहना

सी.पी. राधाकृष्णन ने एम्स रायपुर को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बदलाव का महत्वपूर्ण प्रतीक बताया। उन्होंने संस्थान में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा अनुसंधान और ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने एम्स रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ के पहले

स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने संस्थान की चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धियों को महत्वपूर्ण बताया। दीक्षांत समारोह में 'से नो टू ड्रग्स' अभियान के तहत विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। विद्यार्थियों ने खुद नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने और अपने साथियों व समाज के बीच नशे के दुष्प्रभावों और खतरों को लेकर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में 689 विद्यार्थियों को मिली डिग्री

ढुढुस्र्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 689 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें 376 छात्राएं और 313 छात्र शामिल हैं। समारोह में त्र, क्व्र, सुपर-स्पेशियलिटी, डॉक्टरेट और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। वहीं उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को उपराष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

ये रहे मौजूद समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। ढुढुस्र्स रायपुर की ओर से अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) संजीव हांडा और कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल भी मंच पर उपस्थित रहे। तीसरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान करने के साथ ढुढुस्र्स रायपुर की चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में भूमिका को भी रेखांकित किया गया।

ताजा खबर
संक्षिप्त

जंगल में प्लास्टिक फेंकने वाले पर्यटकों को भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना

रायपुर। आने वाले अक्टूबर से शुरू हो रहे पिकनिक सीजन भारी पड़ सकती है? वीकेंड और छुट्टियों के दौरान पिकनिक मनाने आने वाले लोगों द्वारा जंगलों और नदी तटों के पास भारी मात्रा में अनियंत्रित प्लास्टिक कचरा छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे पर्यटकों की खैर नहीं। उन्हें लाखों का जुर्माना भरना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों (संरक्षित वनों) को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। वनों और वन्यजीवों को प्लास्टिक के खतरों से बचाने के लिए वन क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा कचरा फैलाने पर अब सीधे जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत मैदानी अमले जैसे फारेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को सीधे कार्रवाई करने के अधिकार सौंपे गए हैं। यह मैदानी अमला न्यूनतम 500 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ले सकेगा। इसके बाद भी दोबारा प्लास्टिक कचरा फैलाने पर जुर्माना दोगुना लिया जाएगा। पहली बार फॉरेस्ट गार्ड (वनरक्षक) और डिप्टी रेंजर (उप-वनक्षेत्रपाल) को मौके पर ही जुर्माना वसूलने का कानूनी अधिकार दिया गया है छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और उनके बफर इसके लिए पर्यटकों के वाहनों और सफारी जिप्सियों की प्रवेश द्वारों (परमिट पॉइंट्स) पर गहन तलाशी ली जाएगी। सिंगल-यूज प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन बैग, वेफर्स/स्नैक्स के रैपर और गुटखा-पान मसाला के प्लास्टिक पाउच ले जाने पर रोक लगाई गई है। पर्यटकों को केवल पुनर्चक्रण योग्य कपड़े या कागज के थैले ले जाने की ही अनुमति दी जा रही है वनों में प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर खतरेवन क्षेत्रों में बढ़ते पर्यावरण संकट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है? जिसके कारण हिरण, बारहसिंघा, भालू और अन्य जंगली जानवर खाने के लालच में प्लास्टिक और पॉलिथीन चबा जाते हैं, जिससे उनके पेट में ब्लॉकेज होने से मौत हो जाती है। साथ ही वनों की मिट्टी में प्लास्टिक के सड़ने न होने के कारण माइक्रोप्लास्टिक प्राकृतिक जल स्रोतों और जमीन में मिल रहे हैं, जिससे पेड़-पौधों के विकास पर असर पड़ रहा है।

400 करोड़ के प्रिंटिंग काम से जुड़ा विवादित टेंडर निरस्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का करीब 400 करोड़ रुपए के प्रिंटिंग काम से जुड़ा विवादित टेंडर निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने 7 अगस्त 2026 को जारी ऑनलाइन टेंडर नंबर 469 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का नोटिस जारी किया है। यह टेंडर उस समय विवादों में आया था, जब प्रदेश की प्रिंटिंग फर्मों ने इसकी प्रक्रिया और पात्रता शर्तों को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। स्थानीय मुद्रण कारोबारियों ने आरोप लगाया था कि सरकारी प्रिंटिंग के करोड़ों रुपये के काम में सीमित फर्मों को लगातार अवसर मिल रहा है और टेंडर की कुछ शर्तें छोटे और मध्यम प्रिंटिंग कारोबारियों के लिए मुश्किल हैं। दरअसल शासकीय मुद्रणालय, वित्त विभाग के निर्देशों को धता बताकर संवाद के बजाय स्वयं के द्वारा करोड़ों के टेंडर जारी करता रहा है और कुछ चुनिंदा प्रिंटिंग फर्मों को वर्क आर्डर दिए जाते रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय प्रिंटिंग फर्मों की ओर से की गई शिकायत में पिछले कुछ वर्षों में शासकीय मुद्रणालय के जरिए हुए करीब 400 करोड़ रुपये के प्रिंटिंग कार्यों का जिक्र किया गया था।

भाजपा ने प्रकोष्ठों के प्रभारी, और संयोजक नियुक्त किए

रायपुर। प्रदेश भाजपा के अलग-अलग प्रकोष्ठों के प्रभारी, और संयोजकों की नियुक्ति की है। बताया गया कि नियुक्त पदाधिकारियों में एनक्यू-एनजीओ प्रकोष्ठ के लिए एस.डी. बड़गे, बुनकर प्रकोष्ठ में सीमा साहू, विधि प्रकोष्ठ में जयप्रकाश चंद्रवंशी, चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉ. ललित माखीजा, व्यापार प्रकोष्ठ में श्रीचंद सुंदरानी, व्यवसायी प्रकोष्ठ में प्रदीप सिंह, आरटीआई प्रकोष्ठ में डॉ. विजयशंकर मिश्रा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में मोना सेन, पंचायत प्रकोष्ठ में श्वेता शर्मा, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ में देवजी भाई पटेल, शिक्षा प्रकोष्ठ में राजेश साहू तथा सहकारिता प्रकोष्ठ में विक्रांत सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पांच जिले देश के टॉप-10 में, कोरिया का '5 प्रतिशत मॉडल' बना खास पहल और पानी की कमी वाले ब्लॉक 26 से घटकर 19 हुए

बारिश की बूंदों से भविष्य की सुरक्षा छग का जल मॉडल देश में अव्वल

रायपुर। बारिश की हर बूंद को सहेजने और उसे धरती के भीतर पहुंचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने देश के सामने जनभागीदारी का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। जल शक्ति मंत्रालय के 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य के पांच जिले भी जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाने में सफल रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों और जनभागीदारी आधारित प्रयासों की जानकारी राष्ट्रीय मंच पर साझा की। सम्मेलन के 'कैच द रेन' सत्र में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राज्य में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण तथा पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल सहित विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ का जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण मॉडल

देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को केवल शासकीय योजनाओं और जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रखा है। किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय समुदायों को इससे जोड़कर इसे व्यापक जनअभियान का स्वरूप दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और अपने गृहग्राम बगिया में हल चलाकर खेती कर चुके हैं। इसलिए खेती और ग्रामीण जीवन में पानी का महत्व उन्होंने बहुत करीब से देखा और समझा है। किसान के लिए पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसकी फसल, परिवार, आजीविका और भविष्य से जुड़ा विषय है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण की योजनाओं के केंद्र में किसान और गांव को रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग चार प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला छत्तीसगढ़ 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। यह उपलब्धि केवल जल संरचनाओं की संख्या की नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति प्रदेश में विकसित हो रही सामूहिक चेतना और जनभागीदारी की भी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मेलन में कोरिया जिले से शुरू हुए '5 प्रतिशत मॉडल' का विशेष उल्लेख किया। यह मॉडल जल संरक्षण में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी का अभिनव उदाहरण है। इस पहल के अंतर्गत किसान अपनी कृषि भूमि का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा भू-जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं। इस हिस्से में ऐसी जल संरचनाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें बारिश का पानी खेत से बहकर बाहर जाने के बजाय वहीं एकत्र हो और धीरे-धीरे जमीन के भीतर समाहित हो सके। इस मॉडल की विशेषता यह है कि इसमें किसान जल संरक्षण के केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं। किसान अपनी भूमि उपलब्ध करा रहे हैं, पंचायतें और स्थानीय समुदाय सहयोग कर रहे हैं तथा विभिन्न विभागों और योजनाओं के समन्वय से जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। जल संरचनाओं की जियो-टैगिंग, नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की समीक्षा को भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। जल सखी, जल मित्र, किसान और पंचायत प्रतिनिधि गांवों में जल संरक्षण की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। खेत में ही वर्षा जल को रोकने से भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा मिलने के साथ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना है। लंबे समय में इससे खेती की वर्षा पर निर्भरता कम करने और जल सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। जल शक्ति मंत्रालय के 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के तीनों चरणों में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पहले दो चरणों में देश में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद तीसरे चरण में राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

महिलाओं के संपत्ति अधिकार को मजबूत कर रही विष्णु भैया की सरकार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का सीधा लाभ अब प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। रायगढ़ की श्रीमती शर्मिला मिश्रा ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए जमीन की रजिस्ट्री कराई, जिससे उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई। उन्होंने इस जनहितकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार महिलाओं के नाम पर जमीन एवं अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क की दर को आधा कर दिया गया है। पहले संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता था, जिसे अब महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री के लिए घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने को प्रोत्साहन मिल रहा है। रायगढ़ निवासी श्रीमती शर्मिला मिश्रा ने सरकार की इस सुविधा का लाभ लेते हुए जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई।

छग में अपराध पीड़ितों के 1099 मामलों में 37.07 करोड़ की क्षतिपूर्ति लम्बित

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अपराध पीड़ितों के 1099 मामलों में 37 करोड़ 7 लाख 42 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि फंड की उपलब्धता नहीं होने के कारण लंबित है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत यह राशि पात्र पीड़ितों को दी जानी थी। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2018 के तहत राशि के आवंटन और

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लंबित राशि फंड उपलब्ध होते ही जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया। कोर्ट ने मामले की निगरानी जारी रखते हुए सक्षम अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने योजना के लिए अलग बजट हेड बनाने की जानकारी भी दी थी। डिवीजन बेंच ने सक्षम अधिकारी को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर स्पष्ट रूप से बताने को कहा है कि 37.07 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

अधिकारी को शेष राशि कब तक जारी कर पात्र पीड़ितों को भुगतान किया जाएगा, इसका समयबद्ध विवरण भी देना होगा। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को सूचीबद्ध की गई है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बरसात के समाप्त होते ही निर्माणाधीन पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी निर्माणाधीन कार्यों का एक सप्ताह के भीतर ठेकेदारों के साथ स्थल निरीक्षण कर काम आगे बढ़ाने की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करते हुए बरसात के तुरंत बाद निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में सभी निर्माण स्थलों पर काम होते हुए दिखना चाहिए। श्री बंसल ने आज नवा रायपुर स्थित

पीडब्ल्यूडी मुख्यालय 'निर्माण भवन' में पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन 20 सितम्बर तक जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश से क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत के साथ रेलिंग और दीवारों की पेंटिंग का काम 30 नवम्बर तक पूरा करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में सेतु परिक्षेत्र के सभी संभागों के कार्यपालन अभियंताओं को अपने-अपने संभागों में भ्रमण कर पुल-पुलियों की वास्तविक जरूरत का

आकलन कर लोगों की जरूरतों के अनुरूप नए पुल-पुलियों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने और क्षतिग्रस्त पुलों की स्थिति पर भी लगातार नजर रखने और जहां आवश्यकता हो, वहां नए पुलों के निर्माण के प्रस्ताव भेजने को कहा। श्री बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से निर्माण स्थलों पर जाकर कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

उन्होंने काम में लापरवाही बरतने या कार्य की गति धीमी रखने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कार्यपालन अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में मौजूद रहते हुए निर्माण स्थलों की समस्याओं को तत्परता से निराकृत करने को कहा। श्री बंसल ने नए कार्यों की निविदा प्रक्रिया नवम्बर तक पूरी करने और जनवरी तक सभी कार्य हर हाल में शुरू करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को समय पर ले-आउट, ड्राइंग-डिजाइन और कार्यस्थल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थलों पर आने वाली समस्याओं का तत्परता से समाधान करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गंभीरता से मॉनिटरिंग और निरीक्षण करने के निर्देश दिए। हर महीने करें भुगतान, काम पूरा होने के तीन माह में अनुबंध क्लोज करें लोक निर्माण विभाग के सचिव ने ठेकेदारों को हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रभावित न हो। उन्होंने कार्य पूर्ण होने के बाद तीन माह के भीतर सभी दस्तावेजी प्रक्रिया और भुगतान पूरा कर अनुबंध क्लोज करने को कहा। गतिशक्ति पोर्टल पर 10 सितम्बर तक जानकारी अपलोड करें श्री बंसल ने भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदेश के सभी पुल-पुलियों की जानकारी 10 सितम्बर तक अपलोड करने के निर्देश दिए।

सहायक प्राध्यापक भर्ती में देरी पर जताई नाराजगी

उच्च शिक्षा मंत्री ने ली विभागीय समीक्षा बैठक

बजट और कॉलेज एडमिशन को लेकर दिए सख्त निर्देश

रायपुर। प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के साथ विभागीय कामकाज में तेजी लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने बुधवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 1 जुलाई को हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की गई। कई कार्यों में देरी पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को प्रशासनिक ढिलाई दूर करने और सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने शासकीय महाविद्यालयों में अब तक हुए कम प्रवेश पर भी चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए महाविद्यालय स्तर पर सकारात्मक और प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चंपावत,

आयुक्त रीता यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

700 सहायक प्राध्यापक पदों की भर्ती में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में चल रही प्रवेश प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आ रही रुकावटों को तत्काल दूर करने को कहा। इसके अलावा प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। स्नातक प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों को लेकर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने 15 सितंबर 2026 तक पदोन्नति से संबंधित पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं, अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले प्राध्यापकों के मामलों की जांच और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।

वेतनमान के मामलों में देरी पर जताई नाराजगी

वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान से जुड़े मामलों के लंबित रहने पर भी मंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मामलों के समय पर निराकरण नहीं होने के कारण सहायक प्राध्यापकों को न्यायालय का रुख करना पड़ रहा है। मंत्री ने विभाग में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का पूरा ब्योरा अधिकारियों से मांगा। उन्होंने निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण कर संबंधित आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही शिक्षकों की पीएच.डी. अनुमोदन प्रक्रिया की प्रगति और मंत्री कार्यालय से भेजी गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई की भी विस्तृत जानकारी मांगी गई।

महाविद्यालयवार बजट की पूरी जानकारी देने के निर्देश

बैठक में वित्तीय मामलों को लेकर भी अधिकारियों से जवाब मांगा गया। पिछली बैठक में मांगी गई बजट संबंधी जानकारी अधूरी मिलने पर मंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आवंटित बजट की महाविद्यालयवार पूरी सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मंत्री ने महाविद्यालयों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण कराने के निर्देश दिए

रायगढ़ की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर बढ़ाया देश का मान : वित्त मंत्री

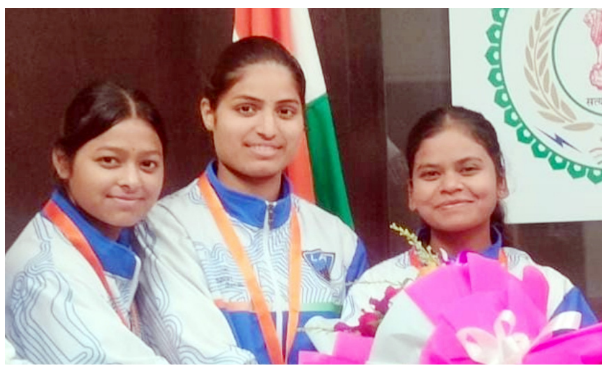

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लैक्रॉस टूनार्मेंट में भारतीय महिला लैक्रॉस टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने रायगढ़ जिले की तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों सोनम बंजारा, शांति प्रधान और मानसी भूमिया को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। भारतीय महिला लैक्रॉस टीम ने टूनार्मेंट में बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। टीम की इस सफलता में रायगढ़ की तीनों खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि रायगढ़ सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। सोनम बंजारा, शांति प्रधान और मानसी भूमिया की सफलता प्रदेश की अन्य बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी।

एशियाई खेलों की तैयारी के लिए स्मार्ट ट्रैक का सहारा ले रहे एथलीट

नई दिल्ली। 19 सितंबर से जापान में होने वाले एशियाई खेलों को देखते हुए भारतीय एथलीट अभ्यास के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं। इसी के तहत ही इन एथलीटों को बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) में एक विशेष ह्यस्मार्ट ट्रैकह्व उपलब्ध कराया गया है। इस ट्रैक पर स्टीपलचेज धावक अविनाश साबले और लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी सहित आठ एथलीट अभ्यास कर रहे हैं। इनका ये अभ्यास शिविर 8 सितंबर तक चलेगा। इससे इनकी, प्रदर्शन क्षमता बेहतर होगी।

इस उच्च-स्तरीय शिविर को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत मंजूरी दी गई है। इसमे शामिल सभी एथलीटों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये प्रतिभाशाली एथलीटों को समर्थन देने का खेल विभाग का प्रयास है। शिविर में शामिल अन्य प्रमुख एथलीटों में 800 मीटर के धावक कृष्ण कुमार, डेकाथलॉन एथलीट तौफीक एन, ऊंची कूद के एथलीट आदर्श राम और सुप्रिया बी, तथा पैदल चाल की खिलाड़ी मंजू रानी और प्रियंका शामिल हैं। ये सभी एथलीट अपने-अपने इवेंट्स में उत्कृष्टता प्राप्त करने और एशियाई खेलों में देश के लिए पदक जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

गौरतल है कि साइ एनसीओई बेंगलुरु में स्थापित यह ह्यस्मार्ट ट्रैकह्व भारत में अपनी तरह का पहला है, जो एथलीटों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। इसमें जब एथलीट दौड़ता है, तो उसी समय उसकी गति से जुड़े आंकड़े मिलते हैं। जहां-जहां ह्यगेटह्व लगाए गए हैं, वहां के ह्यस्प्लिट टाइमिंगह्व के साथ-साथ कुल समय और ह्यस्ट्राइडह्व की लंबाई का भी पता चलता है। ये सभी आंकड़े ह्यरियल टाइमह्व में दर्ज किए जाते हैं, जिससे एथलीटों के प्रशिक्षण में अविश्वसनीय रूप से मदद मिलती है। यह ट्रैक 2024 में स्थापित किया गया था और तब से इसका उपयोग शीर्ष स्तर के एथलीटों द्वारा किया जा रहा है।

इस अत्याधुनिक ट्रैक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कोचों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान एथलीट के प्रदर्शन से जुड़े सटीक और तात्कालिक आंकड़े प्रदान करता है।

भारत दौरे में बेहतर प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बनाना चाहते हैं मर्फी

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई ए टीम के ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को उम्मीद है कि आगामी भारत दौरे में बेहतर प्रदर्शन कर वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बना सकते हैं।

मर्फी का लक्ष्य तीनों ही प्रारुपों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में अपनी दावेदारी मजबूत करना है। मर्फी ऑस्ट्रेलिया ए टीम की ओर से इंडिया ए के खिलाफ चार-दिवसीय और एक-दिवसीय दोनों ही मैचों की सीरीज के लिए शामिल किये गये हैं। उन्हें 22 सितंबर से 11 अक्टूबर तक पुडुचेरी में होने वाले दो चार-दिवसीय और तीन एक-दिवसीय मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है। इसमें बेहतर प्रदर्शन कर वह अगले साल जनवरी और फरवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत दौरे के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं।

इस खिलाड़ी का मानना है कि लाल गेंद वाला मैच उन हालातों की तैयारी के लिए अहम हैं, जिनका सामना उन्हें संभावित टेस्ट दौरे पर करना पड़ सकता है। सीए की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने हाल ही में कहा, उन हालातों में खेलने और वहां अपने कौशलको बेहतर बनाने का कोई भी मौका बहुत अहम होता है। मर्फी ने साथ ही कहा कि इन ए दौरों का लक्ष्य युवा खिलाड़ियों को भारत के हालात और माहौल से परिचित कराना है, ताकि यदि उन्हें टेस्ट दौरे पर मौका मिले, तो वे उन हालातों को जान सकें। उन्होंने पिछले साल के अनुभव से काफी कुछ सीखने की बात कही और इस साल भी उसे बेहतर करने की उम्मीद जताई।

गौरतलब है कि मर्फी ने साल 2023 में नागपुर में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और 7 विकेट लेकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि, अब तक खेले गए उनके सभी 7 टेस्ट मैच विदेशी जमीन पर हुए हैं। वे पिछले साल श्रीलंका के टेस्ट दौरे पर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा थे और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन की अनुपस्थिति में खेलने के लिए तैयार रहते थे।

नाथन लियोन के फिट होने और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट दौरे के दौरान तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों की उम्मीद के बीच, मर्फी का ध्यान भारत ए के खिलाफ सफेद मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने पर भी होगा। उन्हें जून में बांग्लादेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की एकदिवसीय टीम में पहली बार बुलाया गया था, हालांकि वे किसी मैच में नहीं खेले थे।

एकदिवसीय में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकार्ड है सहवाग के नाम

नई दिल्ली। एकदिवसीय क्रिकेट में आक्रामक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम एक ऐसा रिकार्ड है जो आज तक बरकरार है। यहां तक कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इसे तोड़ नहीं पाये हैं। सहवाग ने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में कप्तानी करते हुए एक केवल 149 गेंदों पर 219 रन बना दिये थे। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 25 चौके और 7 छक्के लगाये थे।

टोरेस पीएसजी में शामिल होंगे

बार्सिलोना। बार्सिलोना के स्टार फारवर्ड फेरान टोरेस अब पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) में शामिल होने जा रहे हैं। स्पेन की विश्व कप विजेता टीम के इस स्टार खिलाड़ी को लेकर बार्सिलोना और फ्रांसीसी क्लब पीएसजी के बीच करीब 50 मिलियन यूरो के एक बड़े सौदे पर सहमति बन गई है। दोनों क्लबों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और अब केवल कुछ जरूरी औपचारिकताएं ही बची हैं। बताया जा रहा है कि फेरान टोरेस पीएसजी के साथ पांच साल के करार पर हस्ताक्षर करेंगे, जो उनके करियर को एक नई दिशा देगा।

गौरतलब है कि टोरेस जनवरी 2021 में मैनचेस्टर सिटी से 55 मिलियन यूरो से अधिक की राशि में बार्सिलोना आए थे। हालांकि, स्पेनिश क्लब में उनका सफर हमेशा एक प्रमुख शुरुआती खिलाड़ी के तौर पर नहीं रहा। मुख्य कोच हांसी फ्लिक के आने के बाद, उन्हें अक्सर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के विकल्प के रूप में सेंटर फारवर्ड की भूमिका में इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद, उन्होंने मिले सीमित अवसरों का पूरा लाभ उठाया और अपनी गति, गेंद पर नियंत्रण तथा आक्रमण में कई स्थानों पर खेलने की क्षमता से टीम के लिए कई बार निर्णायक साबित हुए। पिछले दो सत्रों में, उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर 94 मैचों में शानदार 40 गोल दर्ज किए हैं, जो उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।

यह स्थानांतरण ऐसे समय हो रहा है जब टोरेस ने हाल ही में स्पेन की विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पिछले महीने स्पेन और अर्जेंटीना के बीच हुए विश्व कप फाइनल में उन्होंने अतिरिक्त समय में स्पेन के लिए निर्णायक गोल दागा था, जिससे स्पेन ने दूसरी बार प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रीय टीम के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के कुछ ही समय बाद उनका क्लब बदलना फुटबॉल जगत में गहन चर्चा का विषय बन गया है। टोरेस ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत वालेंसिया की युवा व्यवस्था से की थी, जिसके बाद वह मैनचेस्टर सिटी और फिर बार्सिलोना का हिस्सा बने। अब पेरिस सेंट-जर्मेन में उनका जाना उनके करियर को एक नई और महत्वपूर्ण दिशा देने की क्षमता रखता है।

अब डरहम की ओर से काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे मयंक

लंदन। बल्लेबाज मयंक अग्रवाल अब इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खेलते नजर आयेंगे। मयंक पिछले काफी समय से भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाये हैं। ऐसे में उन्होंने काउंटी की ओर रुख किया है।

उनका लक्ष्य काउंटी में बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय टीम में वापसी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना है। मयंक ने डरहम क्रिकेट क्लब के साथ करार किया है। वह इस सीजन के बचे हुए चार मुकाबलों के लिए टीम से जुड़ गए हैं, जो उनके लिए एक नई शुरूआत का प्रतीक है।

अग्रवाल सोमवार को ही इंग्लैंड पहुंच गए और डरहम क्रिकेट टीम से जुड़ गये। क्लब के अनुसार वह नॉर्थम्पटनशर के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह मैच ऐतिहासिक काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा। गौरतब है कि काउंटी क्रिकेट में खेलकर कई बल्लेबाज अपने कौशल को निखारने में सफल रहे है जो उनकी टीम में वापसी का कारक बना है।

गौरतलब है कि डरहम की टीम इस समय काउंटी चैंपियनशिप डिविजन-दो की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर मजबूती से बरकरार है। टीम ने अब तक खेले गए 10 मुकाबलों में सात जीत और तीन ड्रॉ के साथ कुल 191 अंक हासिल किए हैं। ऐसे में मयंक का टीम में शामिल होना न केवल उनके लिए बल्कि डरहम के लिए भी बेहद अहम र्ण है, क्योंकि टीम का मुख्य लक्ष्य इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए डिविजन-एक में पदोन्नति हासिल करना है।

मयंक ने भारतीय टीम की ओर से 21 टेस्ट मैचों में 41.33 की औसत से लगभग 1500 रन बनाए हैं, इसमें चार शानदार शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, जहां उन्होंने निरंतरता के साथ रन बटोरे हैं। उन्होंने अब तक 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 43.98 के कुल औसत से कुल 8929 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 21 शतक और 48 अर्धशतक लगाये हैं।

डरहम के मुख्य कोच रयान कैंपबेल ने मयंक अग्रवाल के टीम में शामिल होने पर अपनी खुशी और उम्मीदें व्यक्त की हैं। उन्होंने बताया कि मयंक के आने से दक्षिण अफ्रीका के डेविड बेडिंगहम की कमी पूरी हो गयी है। । बेडिंगहम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम में जगह मिलने के बाद काउंटी टीम छोड़ दी थी।

कैंपबेल ने अग्रवाल की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा, मयंक बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका रिकार्ड शानदार है। हमें उम्मीद है कि वह डरहम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे, खासकर जब हमारा लक्ष्य काउंटी चैंपियनशिप के डिविजन-एक में वापसी सुनिश्चित करना है।

कारोबार

मच्छरों को भगाने वाला नया डिवाइस फोटॉन मैट्रिक्स तैयार

नई दिल्ली। मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कॉइल, स्प्रे, इलेक्ट्रिक रैकेट और विभिन्न ट्रैप के बाद अब फोटॉन मैट्रिक्स नाम का एक नया उपकरण का निर्माण किया गया है जो उड़ते हुए मच्छरों की पहचान कर उन्हें हवा में ही लेजर की मदद से खत्म करता है।

बताया गया है कि यह सिस्टम आसपास उड़ने वाले छोटे कीड़ों की पहचान करने के बाद उनकी गतिविधियों को ट्रैक करता है। इसके बाद मच्छरों को लक्ष्य बनाकर स्वचालित तरीके से लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिडार और रडार जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस नई तकनीक का उद्देश्य उपयोगकर्ता को हाथ में रैकेट लेकर मच्छरों के पीछे भागने की जरूरत से राहत देना है। कंपनी का दावा है कि यह तकनीक पूरी तरह स्वचालित ढंग से काम कर सकती है। सुरक्षा को लेकर भी उपकरण में विशेष तकनीक शामिल किए जाने का दावा किया गया है। इसे मुख्य रूप से मच्छरों जैसे छोटे कीड़ों की पहचान के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इंसानों, पालतू जानवरों और अन्य बड़े जीवों को लक्ष्य बनाने से बचने के लिए अलग सुरक्षा तंत्र लगाए गए हैं।

हालांकि किसी भी लेजर आधारित उपकरण के वास्तविक सुरक्षा मानकों और प्रभावशीलता का बेहतर आकलन स्वतंत्र परीक्षण और लंबे समय के उपयोग के बाद ही किया जा सकेगा। यह उपकरण खासतौर पर बगीचों, बैकयार्ड और खुले बाहरी क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है, जहां मच्छरों की समस्या अधिक रहती है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 988 डॉलर, यानी लगभग 94 हजार रुपये बताई गई है।

वीवो नई फ्लैगशिप एक्स 500 सीरीज करेगी लॉन्च

नई दिल्ली। चाइनीज कंपनी वीवो अपनी नई फ्लैगशिप एक्स 500 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है। वीवो एक्स 500 सीरीज में वीवो एक्स 500, वीवो एक्स 500 प्रो और वीवो एक्स 500 प्रो मैक्स शामिल होंगे। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस सीरीज के कैमरा फीचर्स को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इनमें सबसे प्रीमियम मॉडल वीवो एक्स 500 प्रो मैक्स को कैमरा क्षमताओं के लिहाज से बेहद दमदार बताया जा रहा है। कंपनी के अनुसार, वीवो एक्स 500 प्रो मैक्स में 200 मेगापिक्सल का जाइस एपीओ सुपर टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। इसमें 1/1.4 इंच आकार का सेंसर, सैमसंग एचपी 0 सेंसर और वीवो की ब्लूप्रिंट इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। फोन में हार्डवेयर आधारित 4एक्स इन-सेंसर जूम तकनीक भी शामिल होगी, जिससे दूर स्थित विषयों की

तस्वीरों में अधिक डिटेल मिलने की उम्मीद है। वीवो एक्स 500 प्रो मैक्स को 400 मिलीमीटर टेलीफोटो एक्सटेंडर के साथ इस्तेमाल करने की सुविधा भी मिल सकती है। यह फीचर खेल, कॉन्सर्ट और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी जैसे मामलों में उपयोगी हो सकता है।

कंपनी इसमें सुपर कैप्चर इंजन भी दे सकती है, जो 30एक्स तक जूम पर तेजी से चल रहे विषयों को कैप्चर करने में मदद करेगा। फोन के मुख्य कैमरे में बेहतर स्टेबलाइजेशन तकनीक दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है। इसमें 3 डिग्री वाइड-एंगल और गिम्बल स्तर का स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मिलने का दावा है।

शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा; रुपया दो माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को मजबूत शुरुआत की। सेंसेक्स 300 से अधिक अंक उछला, जबकि निफ्टी 24000 के स्तर से ऊपर कारोबार करता दिखा। भारतीय रुपये ने भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो महीने का उच्चतम स्तर छू लिया।

तीन दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दिखी। बैंक शेयरों में खरीदारी और वैश्विक बाजारों के मजबूत रुख से बाजार को सहारा मिला। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 334.16 अंक या 0.44 फीसदी चढ़कर 76,904.51 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 95.45 अंक बढ़कर 24,009.90 पर कारोबार करता दिखा।

प्रमुख लाभ पाने वाले शेयरों में टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, एटरनल, लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल थे। वहीं, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, टाइटन, इंडिगो, सन फार्मास्युटिकल्स और आईटीसी में गिरावट दर्ज की गई।

विश्लेषकों ने बताया कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में कमी और विदेशी मुद्रा तरलता के विशेष कार्यक्रम के तहत रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा जमा प्रवाह से बाजार की धारणा को समर्थन मिला।

बाजार में उछाल क्यों आया?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में थोड़ी कमी से बाजार की धारणा में सुधार की संभावना है। रुपये के नजरिए से एक बड़ा सकारात्मक पहलू रियायती अदला-बदली सुविधा के तहत 136 अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा संग्रह है। एफसीएनआर (बी) योजना के तहत जुटाए गए 127 अरब अमेरिकी डॉलर आम अनुमानों से कहीं अधिक हैं। इसका बाजार के लिए यह अर्थ है कि रुपया स्थिर होगा, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों का विश्वास मिलेगा। भारत ने देश की विदेशी मुद्रा तरलता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष केंद्रीय बैंक कार्यक्रम के तहत विदेशी मुद्रा जमा के माध्यम से रिकॉर्ड 127.23 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए। यह बाजार के तनाव की अवधि के दौरान प्रवासी भारतीयों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बताया कि 31 अगस्त तक विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक), या एफसीएनआर (बी) जमा से 127.226 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवाह हुआ। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 6,688.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 2,812.98 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

महिंद्रा की एक्सईवी 9एस और 9ई कारें उपलब्ध होगी बैटरी किराया योजना तहत

नई दिल्ली। स्वदेशी कार निमार्ता कंपनी महिंद्रा ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई को बैटरी किराया योजना के तहत उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने एक्सईवी 9एस की शुरुआती कीमत 12.65 लाख रुपये और एक्सईवी 9ई की 13.90 लाख रुपये रखी है।

सामान्य खरीद व्यवस्था में इनकी शुरुआती कीमत क्रमशः 20.65 लाख रुपये और 21.90 लाख रुपये है। इस नई व्यवस्था के बाद दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती कीमत में करीब 8 लाख रुपये तक की कमी आई है। बैटरी किराया योजना में वाहन की मूल कीमत से बैटरी की लागत अलग कर दी जाती है। इससे ग्राहक को कार खरीदते समय

बैटरी की पूरी कीमत एकमुश्त नहीं चुकानी पड़ती। हालांकि बैटरी के इस्तेमाल के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार अलग से भुगतान करना होगा। महिंद्रा के अनुसार, इस योजना में बैटरी का प्रभावी खर्च 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है। यह गणना 6,975 रुपये की शुरुआती मासिक किस्त और प्रतिदिन औसतन 60 किलोमीटर वाहन चलाने के आधार पर की गई है। वाहन को चार्ज करने में आने वाला बिजली का खर्च इसमें शामिल नहीं होगा।

कंपनी ने अपनी बीई 6 स्पोर्टेक के सभी संस्करणों को भी इस योजना के दायरे में शामिल कर दिया है। इससे पहले यह सुविधा सीमित बैटरी विकल्पों वाले कुछ संस्करणों तक ही उपलब्ध थी। कंपनी का मानना है कि बैटरी की लागत अलग करने से इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती कीमत कम होगी और अधिक ग्राहक इन्हें खरीदने की ओर आकर्षित होंगे। हालांकि कम शुरुआती कीमत का अर्थ यह नहीं है कि वाहन की कुल लागत भी उतनी ही कम होगी। ग्राहकों को बैटरी किराये, मासिक भुगतान, प्रति किलोमीटर खर्च और अन्य वित्तीय शर्तों को ध्यान से समझना होगा।

महत्वपूर्ण ख़बर

जहां 118 नदियां समाती हैं, पर एक बूंद भी बाहर नहीं निकलती

- बिश्केक। किर्गिस्तान की पहाड़ियों में बसी एक ऐसी विशाल झील है, जो अपने अनोखे प्राकृतिक अजूबों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसिक-कुल झील, जिसकी एक अद्भुत तस्वीर अंतरिक्ष से सामने आई है, ने इस रहस्यमयी प्राकृतिक सौंदर्य को सबके सामने ला दिया है। यह एक ऐसी झील है, जिसमें 118 से अधिक नदियां आकर समा जाती हैं, लेकिन इसका एक कतरा पानी भी कभी किसी नदी के जरिए बाहर नहीं निकलता, जो इसे और भी खास बनाता है।

हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जब किर्गिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था, तब वहां मौजूद कैमरों ने इस झील का शानदार दृश्य कैद किया। अंतरिक्ष से देखने पर, चारों तरफ बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां और उनके बीच फैली विशाल नीली झील बेहद अद्भुत और विस्मयकारी नजर आती है। यह नजारा प्रकृति की उस भव्यता को दर्शाता है, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। इस्सिक-कुल समुद्र तल से करीब 1,607 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं और सर्दियों में यहां का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है। इसके बावजूद, यह विशाल झील आमतौर पर सर्दियों में पूरी तरह से जमती नहीं है।

होर्मुज में जंग, स्वेज पर चीनः बदल रहा मध्य पूर्व का पावर मैप

- बीजिंग। एक ओर होर्मुज की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मिस्र यात्रा ने मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। यह दौरा तब हो रहा है जब युद्ध के खतरे के कारण होर्मुज का समुद्री रास्ता बुरी तरह प्रभावित है और वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है। बीते 10 दिनों में होर्मुज से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों की संख्या घटकर औसत 13 से मात्र 4 रह गई है, जबकि यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल व्यापार को संचालित करता है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में तीन नए सदस्य नियुक्त

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुधवार को तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की है। नए ट्रस्टियों में दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के मदन मोहन पांडे और शिकोहाबाद की निर्मला यादव शामिल हैं। इनमें से एक सदस्य को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के दिवंगत नेता अशोक सिंघल का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

दरअसल, कुछ महीने पहले राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी को लेकर विवाद सामने

आया था। इस मामले के बाद मंदिर के रोजमर्रा के प्रबंधन से लेकर दान और उपहारों के व्यवस्थित रखरखाव तक व्यवस्था में बदलाव की मांग उठी थी। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रस्ट के कामकाज और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। इस मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। विवाद के बीच चंपत राय के महासचिव पद से इस्तीफा देने की भी बात सामने आई थी। अब ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति और पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया को मंदिर प्रशासन को और व्यवस्थित एवं पेशेवर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बेलारूस ने भारत को विश्व के 3 ताकतवर देशों में शामिल किया

बिश्केक। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मंच पर बेलारूस ने भारत की जमकर प्रशंसा की। बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने भाषण में भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में शामिल किया, जिसमें विशेष रूप से यह बात गौर करने लायक है कि अमेरिका का नाम इस सूची से गायब था। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। लुकाशेंको ने अपने संबोधन में कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने ही बराबर हैं। हम मानते हैं कि तीन ताकतवर देश हैं- चीन, रूस और भारत आर्थिक रूप से ताकतवर परमाणु देश हैं।

एससीओ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं, जो यूरेशिया के बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सम्मेलन के दौरान जारी घोषणापत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर विशेष जोर दिया गया। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड अपनाए जाने को अस्वीकार्य बताया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस गंभीर खतरे से निपटने का आह्वान किया। संयुक्त बयान में सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की और ईरान पर हुए हमलों की निंदा की। इस बयान को बिश्केक घोषणा-पत्र के नाम से जाना जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एससीओ के अन्य प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर किए। घोषणापत्र में कहा गया है कि सदस्य देशों ने आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल को रोकने के महत्व पर जोर दिया। सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा, सूचना संरक्षण और नए प्रकार के अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में आपसी समन्वय को मजबूत करने पर सहमत हुए। संयुक्त बयान में एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही यह भी कहा कि स्वार्थी उद्देश्यों के लिए ऐसे समूहों का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है।

सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सख्त

पाक की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें बेअसर

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर जारी विवाद अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मुखर हो रहा है। इस संवेदनशील मुद्दे पर भारत ने अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मंच पर इस विषय को उठाकर अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का प्रयास किया, हालांकि उनकी यह कोशिश कोई खास कामयाब नहीं हुई।

अपने संबोधन में पीएम शहबाज शरीफ ने पानी को क्षेत्र की जीवनरेखा बताया और इस बात पर जोर दिया कि पानी को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और साझा जल संसाधनों को लेकर देशों के बीच सहयोग होना चाहिए। शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि समझौतों को उनकी भावना और शब्दों के मुताबिक लागू किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की इस अपील को भारत के साथ चल रहे सिंधु जल संधि विवाद से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा

है। पाकिस्तान लगातार यह दावा करता रहा है कि 1960 की सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का आधार है और इसे लागू किया जाना चाहिए। भारत ने यह कड़ा कदम अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद उठाया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। तब से भारत अपने इस रुख पर अडिग है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के बिना पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है और सिंधु का पानी रुका रहेगा। शहबाज शरीफ की बातों से स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि भारत का दांव बिल्कुल सही पड़ा है और पाकिस्तान अपने किए की सजा भुगत रहा है। विवाद के एक अन्य पहलू में हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला भी शामिल है, जिसने सिंधु जल संधि को कानूनी रूप से लागू माना और संधि के तहत विवाद निपटान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही। पाकिस्तान ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया है।

हालांकि, भारत ने पूरी कार्यवाही को मानने से साफ इंकार किया है। भारत का कहना है कि यह ट्रिब्यूनल अवैध रूप से गठित किया गया है और उसे भारत पर कोई अधिकार क्षेत्र हासिल नहीं है। इस मामले में भारत का रुख साफ है कि उसके हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और उनसे जुड़े फैसले किसी ऐसे ट्रिब्यूनल के आदेश से प्रभावित नहीं होंगे, जिसे वह खुद मान्यता ही नहीं देता।

एससीओ समिट में भारत ने क्यों नहीं किया चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का समर्थन

नई दिल्ली। किर्गिस्तान में एससीओ समिट में चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट पर भारत ने अपने पुराने रुख पर रहते हुए इसका समर्थन नहीं किया है।

साल 2018 में पूर्ण सदस्य बनने के बाद से हर समिट की तरह बिश्केक में भी भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने वाले पैराग्राफ से दूरी बनाई। भारत को इस प्रोजेक्ट पर कई एतराज हैं क्योंकि यह कश्मीर के उन इलाकों से गुजरता हैं, जो भारत का हिस्सा हैं लेकिन उन पर पाकिस्तान का कब्जा है। बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने बीआरआई और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ इसके तालमेल के लिए अपना समर्थन दोहराया। नई दिल्ली ने लगातार बीआरआई का समर्थन करने से इनकार कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एससीओ के आर्थिक एजेंडे में एक जटिलता देखी गई है। साल 2023 के समिट में नई दिल्ली ने एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2030 से दूरी बनाई थी। इस बार भी घोषणापत्र में कहा गया है कि सदस्य देश 2030 तक की अवधि के लिए एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को लागू करना जारी रखेंगे। इसमें कोई स्पष्ट शर्त

नहीं जोड़ी गई है।

एससीओ समिट में अपने भाषण में पीएम मोदी इस बात पर जोर दिया कि कनेक्टिविटी को संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कनेक्टिविटी जो संप्रभुता को नजरअंदाज करती है, वह आखिरकार भरोसा और महत्व दोनों देती है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सदस्य देशों से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील की। एससीओ ने ईरान पर सैन्य हमलों की निंदा की और भारत समेत सभी दस सदस्य देशों के समर्थन किए गए एक घोषणापत्र में संघर्ष के राजनीतिक और डिप्लोमैटिक समाधान का समर्थन किया। हालांकि पिछले साल की तरह इस बार भी इजराइल और अमेरिका का नाम नहीं लिया गया।

बिश्केक घोषणापत्र कहता है कि सदस्य देश ईरान के इलाके पर मिलिट्री हमलों की निंदा करने वाली एससीओ की पहले बताई गई स्थिति को दोहराते हैं। इससे आम नागरिक हताहत हुए और काफी आर्थिक नुकसान हुआ। इस तरह की कार्रवाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर के सिद्धांतों और नियमों का उल्लंघन किया है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) एक आधारभूत ढांचा विकास और संपर्क परियोजना है। इसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जलमार्ग से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। चीन की इस परियोजना का भारत ने लगातार विरोध किया है। दरअसल बीआरआई के तहत बीजिंग सीपीईसी पर काम कर रहा है। यह गलियारा पीओके से होकर गुजरता है। ऐसे में इस पर भारत का कड़ा एतराज रहा है।

लाखों कमाने वाले टेक कर्मचारियों को नौकरी जाने के बाद करना पड़ा कड़ा संघर्ष

नहीं मिली नौकरी तो डिप्रेशन से जूझे, जिंदगी ने सिखाया इनकम, सेविंग करना

नई दिल्ली। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल से निकाले गए कर्मचारियों को आर्थिक संकट के साथ अपनी पहचान और मानसिक स्थिति से भी जूझना पड़ा।

मजबूत रिज्यूम होने के बावजूद कई महीनों तक नौकरी नहीं मिली और कुछ को सामान्य स्तर की नौकरियों के लिए भी आवेदन करना पड़ा।

रिपोर्ट के मुताबिक 37 साल के ब्रिटनी बॉल ने मेटा में करीब पांच साल डॉक्यूमेंटेशन इंजीनियर के तौर पर काम किया। उनकी सालाना आय करीब 1.8 करोड़ रुपए थी। नौकरी जाने के बाद उन्होंने 8 हजार से ज्यादा कंपनियों में आवेदन दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। यहां तक कि टारगेट में कैशियर की नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन रिटेल अनुभव नहीं होने से वहां भी चयन नहीं हुआ। खर्च चलाने के लिए उन्हें अपनी बचत इस्तेमाल करनी पड़ी और वॉशिंगटन डीसी छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। बाद में

उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया।

वहीं 25 साल के जेसन झांग गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और सालाना करीब 1.9 करोड़ रुपए कमा रहे थे। नौकरी जाने के बाद करीब 30 जगह आवेदन दिए, लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ब्रांडिंग शुरू की, जिसके बाद कंपनियां खुद उनसे संपर्क करने लगीं। माइक्रोसॉफ्ट में 23 साल काम कर चुके 62 साल के जो फ्रेंड करीब नौ महीने तक गहरे डिप्रेशन से जूझते रहे। नौकरी के बाद पहली बार उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस का खर्च खुद उठाना पड़ा। उन्होंने बाद में रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। इंटेल के पूर्व कर्मचारी रामकृष्ण को छह महीने में नई नौकरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एक साल बाद भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने खर्च घटाए और अंततः अपनी कंसल्टिंग फर्म शुरू की।

रिपोर्ट के मुताबिक इन कर्मचारियों का अनुभव बताता है कि नौकरी को ही आर्थिक सुरक्षा और पहचान का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक एक से ज्यादा आय के स्रोत, पर्याप्त बचत, निवेश, स्वास्थ्य बीमा और पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान देना जरूरी है। छंटनी के दौर में नौकरी का इंतजार करने के बजाय उद्यमिता और स्वतंत्र काम के विकल्प भी उपयोगी साबित हो सकते हैं।

दिल्ली में थार का कहर

कैंट इलाके में बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली कैंट इलाके में बीती देर शाम तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई. हादसा इतना जोरदार था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही दिल्ली कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे की वजह पता लगाने के लिए घटनास्थल के साथ-साथ आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार को जब्त कर लिया गया है. साथ ही आरोपी चालक को भी पकड़ लिया गया है.

ड्राइवर की हुई पहचान

दिल्ली कैंट इलाके में तेज रफ्तार थार गाड़ी से हादसे मामले में थार चालक की पहचान हो गई है. आरोपी ड्राइवर की पहचान भूपेंद्र के तौर पर हुई है. दिल्ली कैंट पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना स्थल व आस-पास के इलाकों के सीसीटीव्ही फुटेज की जांच की जा रही है. दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में इठर की धारा 281/106(̇) के तहत मामला दर्ज किया गया और थार गाड़ी के ड्राइवर भूपेंद्र (26 साल, निवासी झज्जर, हरियाणा) को गिरफ्तार कर लिया गया. वह रोहिणी में दूध का बूथ चलाता है.

पीछे से कार ने मारी थी

टक्कर

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2 सितंबर को शाम करीब 5 बजे ड्यूटी से लौटते समय दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के एक कर्मचारी ने IOC रेड लाइट के पास सड़क दुर्घटना देखी और तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचना दी. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग दुर्घटना का शिकार हो गए थे; पीछे से आ रही महिंद्रा थार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी थी. दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

नौकरी से लौट रहे थे बाइक सवार

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल फिसल गई थी और पीछे से आ रही थार गाड़ी उससे टकरा गई. मृतकों की उम्र लगभग 45-50 साल थी और वे NDMC, लोधी रोड स्थित अपनी नौकरी से द्वारका के सेक्टर-1 स्थित अपने घर लौट रहे थे.

ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने आ रहा नैंसी ग्रेस

वॉशिंगटन। जेम्स वेब और हबल जैसे ऐतिहासिक मिशनों के बाद, नैंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप खगोल विज्ञान के भविष्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष वेधशाला अभी तक अंतरिक्ष में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अपने निर्धारित प्रक्षेपण की तैयारी के अंतिम चरण में है। रोमन का प्राथमिक लक्ष्य ब्रह्मांड में मौजूद डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को उजागर करना, साथ ही सुदूर ग्रहों की खोज करना है, जो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की अबूझ पहेलियों को सुलझाने में मदद करेगा। यह मिशन ब्रह्मांड के विशाल हिस्से का एक व्यापक सर्वेक्षण करेगा। वैज्ञानिक करोड़ों आकाशगंगाओं का अध्ययन कर डार्क एनर्जी के

प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे ब्रह्मांड के लगातार तेज गति से विस्तार के पीछे की रहस्यमय शक्ति माना जाता है। इसके अतिरिक्त, रोमन डार्क मैटर के वितरण और संरचना पर भी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेगा, जो ब्रह्मांड के निर्माण और विकास को समझने के लिए आवश्यक है। रोमन की एक और प्रमुख विशेषता एक्सोप्लैनेट की खोज है, जिससे हमारी सौर प्रणाली के बाहर मौजूद हजारों संभावित ग्रहों की पहचान हो सकेगी। इसमें एक विशेष कोरोनाग्राफ तकनीक भी शामिल है, जो तारों की चकाचौंध को रोककर उनके आसपास के ग्रहों और धूल के बादलों का सीधा अध्ययन करने की एक नई विधि का परीक्षण करेगी। हबल और जेम्स वेब की तुलना में, रोमन की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल वाइड फील्ड ऑफ व्यू (दृश्य क्षेत्र) है। जहां जेम्स वेब किसी विशिष्ट क्षेत्र की गहराई से जांच करने में माहिर है, वहीं रोमन एक साथ आकाश के बहुत बड़े हिस्से का सर्वेक्षण कर पाएगा। रोमन पूरे क्षेत्र की तस्वीर देगा, जबकि वेब किसी खास खगोलीय वस्तु की बारीकी से पड़ताल करेगा। रोमन का प्राथमिक दर्पण हबल के दर्पण के लगभग समान आकार का है, लेकिन इसकी आधुनिक तकनीक और विशाल कैमरा क्षमता इसे सर्वेक्षण के लिए अनूठा बनाती है। इसका वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट हबल की तुलना में एक साथ कहीं अधिक बड़े आकाशीय क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगा, जिससे वैज्ञानिक कम समय में भारी मात्रा में खगोलीय डेटा जुटा पाएंगे।

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज की तैयारी कर रहा चीन

बीजिंग। अपने महत्वाकांक्षी चांगई-7 मिशन के जरिए चीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज की तैयारी कर रहा है। चंद्रमा के इस क्षेत्र तक सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। चीन के इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले गहरे क्रेटरों में मौजूद पानी और बर्फ की वास्तविक मात्रा, गहराई, स्वरूप और उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना है। यह अभियान चीन के तेजी से विकसित हो रहे अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है और भविष्य में चंद्रमा पर मानव गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने की दिशा में भी अहम साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से चंद्रमा पर पानी के मौजूद होने के संकेत मिलते रहे हैं। खासतौर पर दक्षिणी ध्रुव के स्थायी छाया वाले क्षेत्रों में बर्फ के रूप में पानी होने के पर्याप्त प्रमाण हैं।

हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बर्फ कितनी मात्रा में है, सतह के कितने नीचे मौजूद है और क्या इसे भविष्य में व्यावहारिक रूप से निकाला जा सकता है। इन क्रेटरों में पहुंचना बेहद कठिन है, क्योंकि यहां अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है और तापमान अत्यधिक कम रहता है। चांगई-7 मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और विशेष हॉपर शामिल होगा। मिशन के लिए क्यूकियाओ-2 चंद्र रिले उपग्रह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संचार व्यवस्था में सहायता करेगा। मिशन के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने की संभावना है। हॉपर इस अभियान का सबसे खास हिस्सा होगा, क्योंकि यह पहियों वाले रोवर की तरह केवल जमीन पर चलने के बजाय ऊबड़-खाबड़ इलाके के ऊपर छलांग लगाकर आगे बढ़ सकेगा और गहरे, अंधेरे क्रेटरों तक पहुंचने का प्रयास करेगा।

इन क्षेत्रों में खड़ी दीवारें, पथरीली सतह और लगातार अंधेरा पारंपरिक रोवरों के लिए बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में हॉपर को स्वायत्त रूप से दिशा तय करने और संचार बनाए रखने जैसी जटिल तकनीकी क्षमताओं की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक केवल पानी की मौजूदगी की पुष्टि नहीं करेंगे, बल्कि यह समझने का प्रयास करेंगे कि वह किस रूप में और किन स्थानों पर केंद्रित है।

पीएम मोदी की तरह मेलोनी भी रचेंगी इतिहास, लंबे समय सरकार चलाने का बनेगा रिकार्ड

रोम। अब जॉर्जिया मेलोनी इटली में पीएम के तौर पर रिकार्ड बनाने जा रही हैं। मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार 4 सितंबर को इटली के दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन जाएगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है और खुद जॉर्जिया मेलोनी के लिए एक गुड न्यूज भी है। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मेलोनी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और ऐसे में यह उपलब्धि उनकी इमेज को बुस्ट देने का काम करेगी। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है।

इटली को कभी राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता था। ऐसे देश की पहली महिला पीएम जॉर्जिया मेलोनी 4 सितंबर को एक ही सरकार को लगातार 1,413 दिन चला चुकी होंगी। यह पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी से एक दिन ज्यादा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक बर्लुस्कोनी ने अपने चार कार्यकालों में से एक के दौरान 1,412 दिन तक सरकार चलाई थी।

मेलोनी की दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के प्रमुख नेता मार्को ओस्नाटो ने कहा कि यह उपलब्धि निश्चित रूप से गर्व की बात है। विश्लेषकों का कहना है कि यह रिकॉर्ड पीएम मेलोनी की इमेज को मजबूत कर सकता है। इटली में पिछले 80 साल में करीब 70 सरकारें बन चुकी हैं। अब देश 2027 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी कर रहा है। मेलोनी की पार्टी लगातार जनमत सर्वे में सबसे आगे चल रही है। ऐसा हो सकता है कि मेलोनी 2022 की अपनी चुनावी जीत को फिर दोहरा सकती हैं।

मतदान से जुड़े एक संस्थान के मुताबिक हाल की घटनाओं ने मेलोनी के दोबारा चुनाव जीतने का रास्ता मुश्किल कर दिया है। इस साल न्याय व्यवस्था में सुधार से जुड़े जनमत संग्रह में हार से मेलोनी को झटका लगा था। इस नतीजे से पता चला कि मौजूदा सरकार चला रहे गठबंधन के अलावा भी देश में बहुमत हासिल करने वाला कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प हो सकता है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।